जनता के गोठ

Website- https://www.jantakegoth.com

● वर्ष -01 ● अंक- 276 ● रायपुर, सोमवार 21 सितम्बर 2026 ● हिन्दी दैनिक ● पृष्ठ- 12 ● मूल्य- 2 रुपया ● संपादक- शुभम वर्मा ● PRGI Reg No : CTBIL/25/A1787

संक्षिप्त समाचार

मेरठ के आसमान में सूर्य किरण का शौर्य, तिरंगे की आकृति ने मोहा दर्शकों का मन

मेरठ। मेरठ के आसमान में देशभक्ति और रोमांच का अद्भुत संगम देखने को मिला। भारतीय वायुसेना की विशेष हवाई प्रदर्शन टीम 'सूर्य किरण' ने लड़ाकू विमानों के साथ हैरतअंगेज करतब और विभिन्न हवाई संरचनाओं का प्रदर्शन कर हजारों दर्शकों को रोमांचित कर दिया। विमानों के सटीक तालमेल और शानदार संरचनाओं को देखकर दर्शकों ने जमकर तालियां बजाईं। हवाई प्रदर्शन को देखने के लिए मेरठ और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। सुबह से ही आयोजन स्थल पर लोगों की भीड़ जुटने लगी थी। विशेष रूप से युवा वर्ग में इस आयोजन को लेकर खासा उत्साह दिखाई दिया। नई पीढ़ी के युवाओं की बड़ी भागीदारी ने कार्यक्रम को और आकर्षक बना दिया। भारतीय वायुसेना के जांबाज पायलटों ने लड़ाकू विमानों के साथ एक के बाद एक कई रोमांचक करतब प्रस्तुत किए। विमानों की सटीक संरचना और पायलटों के बीच बेहतरीन तालमेल ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

आप पार्षद के इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा का प्रदर्शन

नई दिल्ली। त्रिलोकपुरी में सफाई कर्मी दीपक की मौत के मामले को लेकर निगम पार्षद विजय कुमार के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है. इसी मांग को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने आम आदमी पार्टी के पार्षद विजय कुमार के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया. प्रदर्शन का नेतृत्व पार्षद प्रियंका गौतम और पूर्व उपमहापौर राजकुमार ढिल्लों ने किया. प्रदर्शनकारियों ने दीपक की मौत के मामले में निष्पक्ष जांच और दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. भाजपा नेताओं और प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि दीपक को कथित तौर पर आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाया गया, जिसके बाद उसे आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा. हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी.प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग पार्षद कार्यालय के बाहर जुटे. कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए दीपक के परिवार को न्याय दिलाने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की.

मानसून की विदाई शुरू, पश्चिमी राजस्थान से लौटने के अनुकूल हुए हालात

नई दिल्ली। देश में दक्षिण-पश्चिम मानसून अब अपने अंतिम दौर में पहुंच गया है। मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार, 19 सितंबर से पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों से मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। हालांकि, मानसून की विदाई शुरू होने के बावजूद देश के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। एक जून से 30 सितंबर के बीच देश में सामान्य रूप से 868.6 मिलीमीटर बारिश होती है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, इस वर्ष अब तक सामान्य के मुकाबले करीब 15 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है।

मॉस्को पर यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला

1600 से अधिक ड्रोन दागे, 2 की मौत-रिफाइनरी में लगी आग...

नई दिल्ली/ एजेंसी

रूस में संसदीय चुनाव के आखिरी दिन यूक्रेन ने अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया है। यूक्रेन की ओर से रात भर में रूस के अलग अलग हिस्सों में 1600 से अधिक ड्रोन दागे गए। इनमें से करीब 450 ड्रोन सीधे राजधानी मॉस्को की ओर भेजे गए थे, जिससे शहर में भारी तबाही मची। इस भीषण हमले में 2 लोगों की मौत हो गई और मॉस्को की प्रमुख तेल रिफाइनरी को गंभीर नुकसान पहुंचा। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबयानिन ने इसे राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया। हमले के दौरान मॉस्को की प्रमुख तेल रिफाइनरी के मुख्य प्लांट को गंभीर नुकसान पहुंचा। रिफाइनरी में आग लगने के बाद आसमान में काले धुएं का बड़ा गुबार दिखाई दिया। हमले का असर राजधानी के रिहायशी इलाकों में भी देखने को मिला। एक यूक्रेनी ड्रोन के 21 मंजिला आवासीय इमारत से टकराने के बाद वहां आग लग गई। आपातकालीन टीमों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मॉस्को क्षेत्र के गवर्नर आंद्रेई वोरोब्योव के मुताबिक, ड्रोन हमले के दौरान मलबे की चपेट में आने से 44 वर्षीय महिला और 74 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। इस घटना में कई लोगों के घायल होने की भी जानकारी सामने आई है। रिहायशी इमारत में आग लगने के बाद राहत और बचाव टीमों ने करीब 400 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इनमें लगभग 70 बच्चे भी

शामिल थे। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने सोशल मीडिया के जरिए हमले की जानकारी साझा की। उनके अनुसार, इस अभियान में यूक्रेन में निर्मित फ्लेमिंगो और पेलिकन मिसाइलों के साथ ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। जेलेंस्की ने दावा किया कि हमले का मुख्य निशाना रूस की तेल, ऊर्जा और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी सुविधाएं थीं। उनके मुताबिक, ऐसे हमलों का उद्देश्य रूस की युद्ध क्षमता को आर्थिक रूप से कमजोर करना है। यूक्रेन लंबे समय से लंबी दूरी के ड्रोन और मिसाइलों के जरिए रूस के भीतर मौजूद सैन्य और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाता रहा है। हालांकि, इस हमले से जुड़े सभी दावों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसकी एयर डिफेंस यूनिट्स ने 1100 से ज्यादा ड्रोन को नष्ट किया। रूसी अधिकारियों के अनुसार, क्रीमिया और काला सागर के ऊपर उड़ रहे कई ड्रोन भी मार गिराए गए। मेयर सोबयानिन ने कहा कि मॉस्को की ओर बढ़ रहे करीब 450 ड्रोन को हवा में ही नाकाम कर दिया गया। रूसी अधिकारियों ने आरोप लगाया कि यह हमला संसदीय चुनाव की प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश थी।

रूस के संसदीय चुनाव के आखिरी दिन हुआ हमला

ड्रोन हमले का दावा ऐसे समय किया गया, जब रूस में संसदीय चुनाव का तीसरा और आखिरी दिन चल रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक, इसे युद्ध शुरू होने के बाद रूस का पहला संसदीय चुनाव बताया गया। चुनाव में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नीतियों का विरोध करने वाले विपक्ष की मौजूदगी बेहद सीमित बताई गई। रूस ने यूक्रेन के उन चार क्षेत्रों में भी मतदान कराया, जिन्हें उसने युद्ध के बाद अपने कब्जे में लेने का दावा किया है, लेकिन जिन पर उसका पूरा नियंत्रण नहीं है। रूसी अधिकारियों के अनुसार, हमले में मॉस्को क्षेत्र में दो लोगों की मौत हुई है, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। गवर्नर आंद्रेई वोरोब्योव ने मृतकों की पहचान 74 वर्षीय पुरुष और 44 वर्षीय महिला के रूप में की। हमले के बाद नुकसान का आकलन किया जा रहा था। अधिकारियों ने प्रभावित इलाकों में हुई क्षति को लेकर विस्तृत जानकारी साझा नहीं की थी। हमले के दौरान मॉस्को की प्रमुख तेल रिफाइनरी के मुख्य प्लांट को गंभीर नुकसान पहुंचा।

आकाश आनंद और उनकी बहन बाहर

बसपा मायावती ने ईशान आनंद को सौंपी कमान...

नई दिल्ली। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने पार्टी और संगठन को लेकर एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक विस्तृत पोस्ट के माध्यम से घोषणा की है कि उनके छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे ईशान आनंद को अब पार्टी में एक सम्मानजनक जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि आकाश आनंद और उनकी बहन को पूरी तरह से संगठनात्मक जिम्मेदारियों से दूर रखा जाएगा। अपने इस फैसले के पीछे की वजहों को स्पष्ट करते हुए मायावती ने कहा कि राजनीति और

समाज सेवा में आगे बढ़ने के लिए भाई-बहनों और रिश्तेदारों के मोह से ऊपर उठना पड़ता है। उन्होंने पार्टी संस्थापक कांशीराम और डॉ. भीमराव अंबेडकर के आदर्शों का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा परिवारवाद से दूरी बनाए रखी।

भारत ने खोला पदकों का खाता

भारत की बेटियों ने रचा इतिहास.....पहले ही दिन सोनम एलावेनिल और विदर्शा सिल्वर मेडल पर जमाया कब्जा

■ चीन की टीम ने इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया और 1904.2 अंक हासिल करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया

नई दिल्ली। एशियन गेम्स 2026 में भारत ने अपना पहला मेडल जीत लिया है। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भारतीय महिला टीम ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। एलावेनिल वलारिवन, सोनम उत्तम मस्कर और विदर्शा के विनोद की तिकड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 1898.0 अंक हासिल किए। चीन ने इस स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता, जबकि जापान तीसरे स्थान पर रहा। भारत की ओर से एलावेनिल वलारिवन, सोनम उत्तम मस्कर और विदर्शा के विनोद ने 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में हिस्सा लिया। तीनों निशानेबाजों ने मिलकर 1898.0 अंक जुटाए और भारत को सिल्वर मेडल दिलाया। भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए दूसरा स्थान हासिल किया।

जापान की टीम ने 1897.1 अंक के साथ कांस्य पदक जीता। चीन की टीम ने इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया और 1904.2 अंक हासिल करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इसके साथ ही चीन ने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक, महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में इससे पहले का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 1902 अंक था, जो चीन ने 2025 एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में बनाया था। इस बार चीन ने अपने ही रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। इस सिल्वर मेडल के साथ भारत ने एशियन गेम्स 2026 में अपने पदकों का खाता खोल दिया है। भारतीय निशानेबाजों की यह उपलब्धि प्रतियोगिता की शुरुआत में ही देश के लिए अहम रही। एशियन गेम्स का उद्घाटन समारोह 19 सितंबर को हुआ था और प्रतियोगिताओं का आयोजन जापान के आइची-नागोया क्षेत्र में किया जा रहा है। भारतीय शूटिंग दल में कई अनुभवी और युवा निशानेबाज शामिल हैं।

राहुल गांधी का पीएम मोदी से सीधा सवाल

दिया जलाने के लिए पैसा हॉस्टल के लिए क्यों नहीं

नईदिल्ली/ एजेंसी

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर जिया जलाने वाले अभियान पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि सरकार के पास दिया जलाने के पैसे पर छात्राओं के लिए हॉस्टल बनाने के लिए पैसे नहीं है। राहुल गांधी ने मध्यप्रदेश के इंदौर में 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में हिस्सा लिया था और इस दौरान एक छात्रा ने राहुल

के सामने अपनी बात रखी थी। राहुल गांधी ने छात्रा की बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रखी। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार के पास दिया जलाने के लिए पैसा है, हमारे हॉस्टल के लिए क्यों नहीं? ये सवाल कल इंदौर में एक छात्रा ने मुझसे पूछा। उन्होंने कहा कि छात्रा ने बताया कि वह गांव से पढ़ने शहर आई। हॉस्टल है नहीं, तो पीजी में रहना पड़ता है। सिर्फ़सुरक्षित रहने में लाखों खर्च हो जाते हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि हर महीने किराए की चिंता, और बेघर होने का डर, इसी में पढ़ाई करनी पड़ती है। कई लड़कियां इसी वजह से पढ़ाई छोड़ देती हैं। केवल इसलिए कि रहने की जगह नहीं है। और आवास भत्ता? महंगाई के साथ बढ़ता नहीं, ऊपर से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। उन्होंने पीएम मोदी से पूछा कि उस बच्ची के सवाल का कोई जवाब है आपके पास?

दिल्ली हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी का भंडाफोड़,2.168 किलो सोना जब्त

नई दिल्ली। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क विभाग की हवाई खुफिया इकाई ने सोने की तस्करी के एक बड़े मामले का खुलासा किया है। दुबई से आने वाली उड़ान के जरिए भारत में अवैध रूप से सोना लाने के आरोप में एक महिला और एक पुरुष यात्री को पकड़ा गया है। दोनों के कब्जे से कुल 2 किलो 168 ग्राम सोना बरामद किया गया है। सीमा शुल्क अधिकारियों के अनुसार, कार्रवाई पुख्ता खुफिया सूचना और यात्रियों की संदिग्ध गतिविधियों की पहचान के आधार पर की गई। दुबई से उड़ान भरने वाली उड़ान संख्या ईके-514 से आए एक महिला और एक पुरुष यात्री पर अधिकारियों की विशेष नजर थी।

नंदीग्राम उपचुनाव सें पहले कांग्रेस को लगा झटका

उम्मीदवार मिलन प्रधान को तीन अक्टूबर तक जेल में..

कोलकाता/ एजेंसी

पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव से पहले कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान की गिरफ्तारी को लेकर नया अपडेट आया है. 2007 के नंदीग्राम आंदोलन से जुड़े पुराने हत्या मामले में हुई गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. अब वे चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे. वहीं, 4 अक्टूबर को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है. उपचुनाव से पहले हुई कांग्रेस के नंदीग्राम सीट

के उम्मीदवार मिलन प्रधान की गिरफ्तारी के बाद शनिवार को कोर्ट ने 3 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. पश्चिम बंगाल में उपचुनाव को लेकर सियासी पैंतरेबाजी के बीच अब कांग्रेस के नंदीग्राम उपचुनाव के उम्मीदवार मिलन प्रधान की मुश्किलें बहुत ही ज्यादा बढ़ गयी. उपचुनाव से पहले कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान की गिरफ्तारी ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है. शनिवार को हल्दिया सब डिविजनल कोर्ट में पेश किए जाने के दौरान गिरफ्तार कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान ने दावा किया कि टीएमसी डरी हुई है. उनकी गिरफ्तारी के विरोध में शनिवार को हल्दिया सब-डिस्ट्रिक्ट कोर्ट परिसर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने भी प्रदर्शन किया. वहीं, पश्चिम बंगाल पुलिस ने इस मामले में जानकारी दी है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी से की सौजन्य भेंट

छत्तीसगढ़-ओडिशा के आपसी सहयोग,विकास और जनकल्याण से जुड़े विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा

रायपुर। संवाददाता

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज ओडिशा प्रवास के दौरान भुवनेश्वर में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी से उनके निवास पर सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री माझी ने साय का आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच छत्तीसगढ़ और ओडिशा के आपसी सहयोग, विकास एवं जनकल्याण से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ और ओडिशा पड़ोसी राज्य होने के साथ ही सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से भी एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच भी आत्मीय संबंध हैं। विकास और जनकल्याण से जुड़े विषयों पर दोनों राज्यों के बीच बेहतर समन्वय से नागरिकों को लाभ मिलने के साथ ही पूरे क्षेत्र की प्रगति को भी नई गति मिलेगी। सीएम विष्णुदेव ने भेंट-मुलाकात के बाद पत्रकारों से भी चर्चा की। इस दौरान उन्होंने महानदी जल विवाद पर बोले- ''महानदी जल विवाद का अब कोई मामला नहीं है, चूंकि दोनों प्रदेशों में भाजपा की सरकार है। छत्तीसगढ़ में भी, ओडिशा में भी और केंद्र में भी एनडीए की भाजपा सरकार है। इसलिए कहीं कोई विवाद की स्थिति नहीं है और बहुत जल्दी इसका निपटारा होने वाला है।''इंदौर में हुई राहुल गांधी की सभा पर बोले-''राहुल गांधी का पिछला रिकॉर्ड उठा लीजिए, वो जहाँ-जहाँ भी गए हैं वहाँ पर कांग्रेस का बंटाधार ही हुआ है। डीयू के छात्रसंघ चुनाव के

परिणाम से आप पता लगा सकते हैं की देश का युवा किनके साथ है...

सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों पर जोर

मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दोनों राज्यों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों का उल्लेख करते हुए कहा:छत्तीसगढ़ और ओडिशा केवल भौगोलिक रूप से पड़ोसी राज्य नहीं हैं, बल्कि दोनों राज्यों के बीच गहरा सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जुड़ाव रहा है. सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के बीच आपस में मजबूत आत्मीय संबंध हैं.

बेहतर समन्वय से मिलेगी विकास को गति

दोनों मुख्यमंत्रियों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि बुनियादी ढांचे, जनकल्याणकारी योजनाओं और सीमावर्ती सुरक्षा व विकास के मुद्दों पर दोनों राज्यों के बीच बेहतर समन्वय अत्यंत आवश्यक है. मुख्यमंत्री साय ने विश्वास जताया कि परस्पर सहयोग और रणनीतिक समन्वय से न केवल दोनों राज्यों के नागरिकों को सीधा लाभ पहुंचेगा, बल्कि पूरे मध्य-पूर्वी क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक प्रगति को भी एक नई दिशा मिलेगी.

राहुल गांधी के दौरों पर सीएम साय का निशाना

राहुल गांधी के अलग-अलग राज्यों में हो रहे राजनीतिक दौरों को लेकर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि उनके पिछले दौरों का रिकॉर्ड देखा जाए तो जिन-जिन जगहों पर वे गए, वहां कांग्रेस को नुकसान हुआ। मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी के आगामी मध्य प्रदेश दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि अब इंदौर और मध्य प्रदेश में भी इसका असर देखने को मिलेगा। सीएम साय का यह बयान ऐसे समय आया है, जब राहुल गांधी अलग-अलग राज्यों में राजनीतिक कार्यक्रमों और दौरों में शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के पिछले प्रदर्शन का हवाला देते हुए राहुल गांधी के राजनीतिक दौरों के प्रभाव पर सवाल उठाया।

रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के बीच 26वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन

–बस्तर संभाग बना ऑल ओवर चैंपियन, वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने खिलाड़ियों से कहा–खेल को बनाएं कैरियर

भुजबल बघेल

बकावंड जनता के गोठ 20 सितम्बर 2026/ स्थानीय धरमपुरा स्थित क्रीड़ा परिसर जगदलपुर में आयोजित 26 वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता 2026-27 का शनिवार को रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के बीच भव्य समापन हुआ। समापन समारोह के मुख्य अतिथि वन मंत्री श्री केदार कश्यप रहे, जबकि अध्यक्षता जगदलपुर महापौर श्री संजय पांडे ने की। पांच संभागों से पहुंचे करीब 700 खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर खेल प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।

यहाँ पर तीन खेलों एथलेटिक्स, हैंडबॉल और रग्बी में बालक-बालिकाओं के विभिन्न आयु वर्गों में हुए मुकाबलों में खिलाड़ियों ने पूरे जोश और खेल भावना के साथ भाग लिया। प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए बस्तर संभाग ने ऑल ओवर चैंपियनशिप अपने नाम कर लिया। टीम गेम में बस्तर का दबदबा हैंडबॉल बालक अंडर-17 वर्ग में बस्तर संभाग प्रथम, रायपुर द्वितीय और दुर्ग तृतीय स्थान पर रहा। हैंडबॉल बालिका अंडर-17 में भी बस्तर ने प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि सरगुजा द्वितीय और रायपुर तृतीय रहा। रग्बी बालक अंडर-17 में बिलासपुर प्रथम, रायपुर द्वितीय और बस्तर तृतीय स्थान पर रहा। रग्बी बालिका अंडर-17 में रायपुर प्रथम, बस्तर द्वितीय और दुर्ग तृतीय रहा। इन परिणामों के आधार पर बस्तर संभाग ने ओवरऑल चैंपियनशिप हासिल कर प्रतियोगिता में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई।

खेल अब सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं -वन मंत्री श्री केदार कश्यप

इस अवसर पर मुख्य अतिथि वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि आज के समय में खेल केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है,

बल्कि खिलाड़ियों के लिए एक बेहतर कैरियर का रास्ता भी है। उन्होंने कहा कि बच्चों को अपनी रुचि और प्रतिभा के अनुसार किसी एक खेल को चुनकर लगातार अभ्यास करना चाहिए।उन्होंने खिलाड़ियों से कहा कि मैदान में जीत के लिए मेहनत जितनी जरूरी है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए अनुशासन और धैर्य भी उतना ही जरूरी है। हार से निराश होने के बजाय उससे सीख लेकर अपनी कमियों को दूर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि गांव और दूरस्थ अंचलों में छिपी खेल प्रतिभाओं को सामने लाने के लिए ऐसे आयोजन महत्वपूर्ण हैं। वन मंत्री श्री कश्यप ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि बस्तर की धरती प्रतिभाओं से भरी हुई है। यहां के खिलाड़ी यदि सही प्रशिक्षण और अवसर के साथ आगे बढ़ें तो राज्य और देश का नाम रोशन कर सकते हैं। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को भविष्य में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दीं। इस मौके पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महापौर श्री संजय पांडे ने कहा कि जगदलपुर में इतनी बड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन शहर के लिए गौरव की बात है। प्रदेशभर से आए खिलाड़ियों ने यहां अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि खेल बच्चों के शारीरिक विकास के साथ उनके व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और टीम भावना को भी मजबूत करता है। बस्तर में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। आवश्यकता है कि इन प्रतिभाओं को बेहतर सुविधाएं, प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं के अवसर मिलते रहें। उन्होंने सभी खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों का स्वागत करते हुए सफल आयोजन के लिए शिक्षा एवं खेल विभाग को बधाई दी।

बस्तर की संस्कृति से सजा समापन समारोह समापन अवसर पर आयोजित रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र रहा। विद्यार्थियों एवं कलाकारों ने बस्तर की लोक संस्कृति, पारंपरिक नृत्य, लोक संगीत और कला पर आधारित मनमोहक प्रस्तुतियां दीं। पारंपरिक वेशभूषा और लोक वाद्यों की प्रस्तुतियों ने पूरे खेल परिसर को बस्तर की संस्कृति से सराबोर कर दिया। खिलाड़ियों और दर्शकों ने तालियों के साथ कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। इस समारोह में सभापति खेल एवं युवा कल्याण जिला परिषद श्री वनवासी मौर्य, जिला आयुक्त स्काउट एवं गाइड श्री सुरेश गुप्ता, और एमआईसी सदस्य श्री संग्राम सिंह राणा एवं श्री नरसिंह राव एवं अन्य जनप्रतिनिधि सहित संयुक्त संचालक स्कूल शिक्षा श्री एचआर सोम, डीईओ श्री बलिराम बघेल, डीएमसी श्री अशोक पांडे तथा शिक्षा व खेल विभाग के अधिकारी, प्रशिक्षक, निर्णायक, खिलाड़ी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

खेत में बिछाए नंगे बिजली तार की चपेट में आया ग्रामीण, मौत के मामले में आरोपी गिरफ्तार

बलरामपुर (जनता के गोठ) : बलरामपुर जिले के त्रिकुंडा थाना क्षेत्र के गोवर्धनपुर, सुईदोहर से एक दर्दनाक मामला सामने आया है। खेत में कथित तौर पर बिछाए गए नंगे बिजली के तार की चपेट में आने से एक ग्रामीण की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने 24 वर्षीय युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

पुलिस के अनुसार, मृतक लहन राम, उम्र 40 वर्ष, 8 सितंबर 2026 को अपने बाड़ी में जुताई करने गया था। इसी दौरान पानी पीने के लिए वह रास्ते से जा रहा था। आरोप है कि इसी रास्ते में राम सिंह के मक्का बाड़ी में सेंट्रिंग के नंगे तार लगाए गए थे, जिनमें बिजली का करंट प्रवाहित किया जा रहा था।

इसी दौरान लहन राम नंगे बिजली तार की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

घटना की सूचना के बाद त्रिकुंडा पुलिस ने मर्ग क्रमांक 39/2026 कायम कर जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, सूचक और गवाहों के बयान दर्ज किए तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विद्युत विभाग से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर

मामले की जांच आगे बढ़ाई।

पुलिस जांच में आरोपी राम सिंह पिता सुधु राम, उम्र 24 वर्ष, निवासी गोवर्धनपुर के खिलाफ जानबूझकर विद्युत लाइन से तार खींचकर मक्का बाड़ी में नंगे तार से करंट प्रवाहित करने का आरोप सामने आया। जांच के आधार पर त्रिकुंडा पुलिस ने अपराध क्रमांक 67/2026, धारा 105 बीएनएस और विद्युत अधिनियम 2005 की धारा 135 के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी राम सिंह को 19 सितंबर 2026 को गिरफ्तार किया और न्यायिक रिमांड के लिए न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल दाखिल कर दिया गया।

सोशल मीडिया पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ अभद्र टिप्पणी को लेकर कांग्रेस का विरोध

अंचल वर्मा - दुर्ग, उतई। जनता के गोठ।

दुर्ग। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पाटन विधायक भूपेश बघेल के विरुद्ध सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर की गई कथित अभद्र, अमर्यादित एवं आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग (ग्रामीण) ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर के आह्वान पर शनिवार को दुर्ग (ग्रामीण) जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के थाना एवं पुलिस चौकियों में कांग्रेसजनों ने पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई और मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की मांग की।

जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर स्वयं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ अमलेश्वर थाना पहुंचे और संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट के संबंध में पुलिस को शिकायत सौंपी। शिकायत के साथ संबंधित पोस्ट के स्क्रीनशॉट, फेसबुक प्रोफाइल का ऋ, कमेंट्स सहित उपलब्ध डिजिटल साक्ष्य भी पुलिस को सौंपे गए, ताकि मामले की निष्पक्ष एवं तकनीकी जांच की जा सके।

शिकायत में उल्लेख किया गया है कि फेसबुक पर नीतीश मंडल नाम से संचालित प्रोफाइल से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संबंध में कथित तौर पर आपत्तिजनक एवं अमर्यादित भाषा में पोस्ट प्रसारित की गई। शिकायतकर्ताओं ने फेसबुक प्रोफाइल की जानकारी एवं उपलब्ध डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर संबंधित व्यक्ति की पहचान कर उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रोफाइल विवरण के अनुसार संबंधित व्यक्ति पूर्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल पखांजूर, जिला कांकेर का पदाधिकारी रह चुका है।

जिला कांग्रेस अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने कहा कि किसी भी सार्वजनिक व्यक्ति के विरुद्ध सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक एवं अमर्यादित भाषा का प्रयोग स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर लगातार इस प्रकार की टिप्पणियों से राजनीतिक एवं सामाजिक वातावरण प्रभावित होता है। पुलिस प्रशासन को उपलब्ध डिजिटल साक्ष्यों की

तकनीकी जांच कर तथ्यों के आधार पर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध शीघ्र वैधानिक कार्रवाई करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। यदि पुलिस द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर शीघ्र एफआईआर दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है, तो कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से व्यापक आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।

जिलेभर में कांग्रेसजनों ने थानों-चौकियों में पहुंचकर दर्ज कराया विरोध जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर के आह्वान पर पाटन, अहिवारा, धमधा एवं दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों के विभिन्न थाना एवं पुलिस चौकी क्षेत्रों में कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे और संबंधित पुलिस अधिकारियों को शिकायत पत्र सौंपा। पाटन विधानसभा क्षेत्र में पाटन थाना सहित विभिन्न स्थानों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर मामले में कार्रवाई की मांग की। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गृह एवं निर्वाचन क्षेत्र पाटन में बड़ी संख्या में कांग्रेसजन थाना पहुंचे और सोशल मीडिया पोस्ट की जांच कर जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। जामगांव-आर एवं रानीतराई थाना में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राजेश ठाकुर के संयोजन में कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता पहुंचे और शिकायत पत्र सौंपा। वहीं अमलेश्वर थाना में मंडल अध्यक्ष महेंद्र साहू के संयोजन में कांग्रेसजनों ने थाना प्रभारी को लिखित शिकायत दी। कुम्हारी क्षेत्र में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मनहरण यादव के संयोजन में कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्रित हुए और मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। अहिवारा विधानसभा क्षेत्र में पुलिस चौकी जेवरा-सिरसा में जिला कोषाध्यक्ष विक्रांत अग्रवाल के संयोजन में कांग्रेसजनों ने शिकायत दर्ज कराई। वहीं थाना भिलाई-3 में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्रीकांत वर्मा के संयोजन में कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधिकारियों से मुलाकात कर मामले की जांच एवं कार्रवाई की मांग की। थाना नंदिनी नगर में अहिवारा ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष उमेश साहू एवं अहिवारा नगर अध्यक्ष संतोष बाफ्ना के संयुक्त संयोजन में कांग्रेसजन थाना पहुंचे। थाना जामुल में जामुल ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कमलेश साहू के संयोजन में कार्यकर्ताओं ने शिकायत सौंपकर मामले में नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की मांग की।

एसईसीएल दीपका क्षेत्र के अधीन संचालित जय अम्बे कंपनी में ड्राइवर मजदूरों से जुड़ी समस्याओं को लेकर छत्तीसगढ़ क्रांति सेना ने खोला मोर्चा

कोरबा। एसईसीएल दीपका क्षेत्र के अधीन संचालित जय अम्बे कंपनी में ड्राइवर मजदूरों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना ने मोर्चा खोला। संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष उमागोपाल के नेतृत्व में कार्यकर्ता एसईसीएल दीपका प्रोजेक्ट के महाप्रबंधक (जीएम) से मुलाकात करने पहुंचे। संगठन की ओर से कंपनी में ड्राइवर मजदूरों की संख्या, एक कर्मचारी को काम से बैठाए जाने, मजदूरों को समय पर भुगतान नहीं मिलने सहित कई शिकायतें जीएम के समक्ष रखी गई। संगठन ने यह आरोप भी लगाया कि कंपनी के अंदर कुछ अधिकारियों द्वारा ड्राइवर मजदूरों से कथित रूप से पैसे लिए जाने की शिकायत सामने आई है। मजदूरों की समस्याओं को लेकर संगठन के कार्यकर्ताओं ने एसईसीएल दीपका प्रोजेक्ट कार्यालय परिसर में नारेबाजी की। इस दौरान कार्यालय परिसर में काफी देर तक नारे गूंजते रहे। मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रोजेक्ट जीएम ने जय अम्बे कंपनी के अधिकारियों से बातचीत की और मजदूरों की शिकायतों के समाधान को लेकर चर्चा की। बातचीत के बाद संबंधित कर्मचारी को दोबारा काम पर रखने की बात सामने आई।

इस दौरान छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष उमागोपाल ने कहा कि ड्राइवर और मजदूरों के साथ किसी भी तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

जीते जीयत सरग नरक बनगे

जीते जीयत सरग ला नरक
बनत देखेंव।
धधकत अपन करेजा ला
उजरत मैहा देखेंव।
मोला बचालेव नइते घुट घुट
के मरहू।
जेन पेड़ ला काटेव ओकरे बर
तरसहू।
करिया सोना बर अपन जिनगी
ला भुला गेव।
रुख राई संग सब्बो जीव जंतु
ला मार देव।
बिना हवा पानी के कैसे रही
सकहू।
चार दिन के जियइया दुयेच
दिन मा मरहू।।

आज देखत हस ये विनास।
जो काहत आरो लेवत हे
विकास।

बिलख बिलख के मैहा रोवत
आरो कोनो मोर सुनव।
जल जमीन उजारे म,कहां
विकास हे तुम गुणव।
तोर जमीन ले तेल निकालही
नत्थी पैसा कमाही।
अऊ तोरे घर में राज करही
बनिहार तोला बनाही।
विकास नाम के पाठ पढ़ाके
तुहिल आंखी देखाही।।

का गरीब ल गरीब बनाना ईही
हरे तुहर विकास।
नि चाही ये विकास हो जाए
सत्यानास।
मोर बर कुछ पीरा नई हे पीरा
हे मोर लइका बर।
जांगर टोर कमावत तभो
तरसत दाना दाना बर।
गऊंहा डोमी कस डस डारिस
अब जागव रे परबुधिया हो।
कब तक सुते बैठे रईहु हक बर
लड़व भगाए के खालव किरिया हो।

योगिता साहू फुलकईना नोनी
ग्रामङ्घचोरभट्ठी(कुरूद)
जिलाङ्घधमतरी,छत्तीसगढ़

पूर्व मुख्यमंत्री , विधायक पाटन भूपेश बघेल के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने के विरोध में नगर कांग्रेस कमेटी उतई ने सौंपा ज्ञापन की गिरफ्तारी की मांग

अंचल वर्मा - दुर्ग, उतई। जनता के गोठ। उतई न्यूज - । पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विरुद्ध फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी करने के विरोध में नगर कांग्रेस कमेटी उतई अध्यक्ष प्रहलाद वर्मा के नेतृत्व में उतई थाना प्रभारी मोहन भारद्वाज को ज्ञापन सोपा गया और निष्पक्ष कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया गया । इस दौरान जिला सचिव बहादुर सिंह नेताम नेता प्रतिपक्ष द्वारिका साहू पूर्व पार्षद वीरेंद्र गोस्वामी पूर्व एल्डरमैन प्रेम नारायण साहू मंडल उपाध्यक्ष भावेस साहू कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता टीकम डोंडे धनंजय नेताम शुभम बमभोले मीडिया प्रभारी गुलशन शर्मा प्रेम पेंटर खिलेंद्र अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे

नौकरी लगाने के नाम पर 2.02 लाख की ठगी का आरोप, युवक गिरफ्तार

फर्जी नियुक्ति पत्र भेजकर रकम लेने का आरोप; मोबाइल जब्त, आरोपी न्यायिक रिमांड पर

बलरामपुर (जनता के गोठ) : नौकरी लगाने के नाम पर कथित रूप से ?2.02 लाख लेने और बाद में फर्जी नियुक्ति पत्र भेजने के मामले में चलगली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक ङ्कद्ब1श कंपनी का मोबाइल फोन भी जब्त किया है।

पुलिस के अनुसार, 10 सितंबर 2026 को थाना चलगली में प्रार्थी रामऔतार, उम्र 29 वर्ष, निवासी चलगली ने लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि उसके रिश्ते का भांजा आशीष सिंह, निवासी सरस्वतीपुर ने नौकरी लगवाने का भरोसा देकर उससे अलग-अलग माध्यमों से रकम ली।

ऑनलाइन भुगतान से लेकर नकद रकम तक

शिकायत के मुताबिक, आरोपी ने ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कराने की बात कहकर प्रार्थी से दस्तावेज लिए और रकम की मांग की। प्रार्थी के अनुसार, अलग-अलग तारीखों में फोन-पे/बैंक भुगतान के माध्यम से रकम भेजी गई तथा कुछ रकम नकद भी दी गई। शिकायतकर्ता ने कुल ?2,02,000 दिए जाने की बात कही है।

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि रकम लेने के बाद आरोपी ने फर्जी नियुक्ति पत्र व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा। बाद में आरोपी ने पासबुक और पैन कार्ड की जानकारी भी मांगी। नौकरी नहीं लगने पर जब रकम वापस मांगी गई तो कथित रूप से आरोपी द्वारा टालमटोल की जाती रही।

19 सितंबर को आरोपी गिरफ्तार

विवेचना के दौरान आरोपी आशीष पिता रामदिल, उम्र 21 वर्ष, निवासी सरस्वतीपुर, चौकी रनहत, थाना चलगली ने 19 सितंबर 2026 को एक ङ्कद्ब1श कंपनी का मोबाइल पुलिस के समक्ष पेश किया, जिसे पुलिस ने जब्ती पत्रक के अनुसार जब्त कर लिया।

पुलिस के मुताबिक, पूछताछ एवं विवेचना के दौरान आरोपी द्वारा घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार किए जाने के बाद उसे 19 सितंबर 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

पुलिस टीम की कार्रवाई

मामले की कार्रवाई में निरीक्षक कुमार चंदन सिंह, प्रधान आरक्षक 405 विष्णुकांत मिश्रा, साइबर आरक्षक 1085 आकाश तिवारी एवं महिला आरक्षक 708 विनीता यादव शामिल रहे।

खबर का असर: भैंसों से भरी पिकअप पलटने के मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन, वाहन मालिक गिरफ्तार

एक भैंसे की मौत, तीन गौशाला भेजे गए; क्क4ष्टञ्ज3854 पिकअप जब्त, आरोपी न्यायिक रिमांड पर

रोहित यादव / बलरामपुर (जनता के गोठ) बलरामपुर जिले के चलगली थाना अंतर्गत ग्राम रामपुर में भैंसों से भरी पिकअप के खेत में पलटने और चालक के मौके से फरार होने को लेकर उठाए गए सवालों के बाद अब मामले में पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। ÷जनता के गोठ÷ में खबर प्रकाशित होने के बाद मामले की जांच आगे बढ़ी और पुलिस ने पिकअप वाहन के मालिक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया।

पुलिस के अनुसार, 09 सितंबर 2026 को सूचना मिली थी कि एक पिकअप वाहन में भैंसों को कथित रूप से क्रूरतापूर्वक ठूंस-ठूंसकर कटिंग के लिए ले जाया जा रहा था। इसी दौरान हरिनारायण के घर के पास वाहन पलट गया। सूचना की तस्दीक के लिए चलगली पुलिस टीम मौके पर पहुंची।

एक भैंसे की मौत, तीन सुरक्षित बरामद

विवेचना के दौरान घटनास्थल से पिकअप वाहन क्रमांक क्क4ष्टञ्ज3854 और तीन भैंसों को गवाहों की मौजूदगी में जब्त किया

गया। हादसे में एक भैंसे की मौत हो गई, जिसका पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया। वहीं बरामद तीनों भैंसों को देखरेख के लिए गौशाला बासेन भेजा गया है।

फरार चालक की तलाश से शुरू हुई पड़ताल, वाहन मालिक तक पहुंची पुलिस

घटना के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने वाहन की पतासाजी शुरू की। जांच के दौरान पिकअप वाहन के स्वामी राजदेव यादव, पिता बलदेव यादव, उम्र 21 वर्ष, निवासी ग्राम लुरगीकला की पहचान हुई।

पुलिस के मुताबिक, विवेचना में आरोपी द्वारा अपने वाहन में भैंसों को कथित रूप से क्रूरतापूर्वक लोड कर कटिंग के लिए दूसरे राज्य ले जाने के संबंध में साक्ष्य पाए गए। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया।

इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला

पुलिस ने मामले में छत्तीसगढ़ राज्य कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004 की धारा 4, 6 एवं 10 तथा पशु क्रूरता अधिनियम, 1960 की धारा 11(1)(घ) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है।

खबर के बाद कार्रवाई से उठे सवालों को मिला जवाब

घटना के बाद यह सवाल उठ रहा था कि आखिर रात के समय भैंसों को पिकअप में भरकर कहां ले जाया जा रहा था और दुर्घटना के बाद चालक वाहन छोड़कर क्यों फरार हो गया। पुलिस की कार्रवाई के बाद मामले में एक महत्वपूर्ण कड़ी सामने आई है। हालांकि, पशुओं को कहां से लाया गया था और उनके परिवहन से जुड़े अन्य पहलुओं की पूरी जानकारी विवेचना पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।

जनता के गोठ की खबर का असर

पिकअप पलटने की खबर के बाद उठे सवालों को पुलिस ने गंभीरता से लिया और जांच आगे बढ़ाई। वाहन जब्ती से लेकर आरोपी की गिरफ्तारी तक हुई कार्रवाई ने मामले को नया मोड़ दिया है। अब पुलिस की आगे की विवेचना पर नजर रहेगी कि इस पूरे पशु परिवहन मामले से जुड़े अन्य लोगों और तथ्यों का क्या खुलासा होता है।

मामले में पुलिस की विवेचना लगातार जारी है।

पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर पूर्व माध्यमिक शाला में हुआ आयोजन

सांकरा में 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत न्योता भोज आयोजित, अतिथियों ने बच्चों संग ग्रहण किया भोजन

चित्रलेखन व भाषण प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने दिखाई अपनी प्रतिभा

सांकरा । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे 'सेवा संकल्प अभियान' के अंतर्गत ग्राम सांकरा स्थित पूर्व माध्यमिक शाला में भव्य 'न्योता भोज' का आयोजन किया गया। भाजयुमो मंडल अध्यक्ष एवं सरपंच रवि सिंगौर की पहल पर आयोजित इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को पोषणयुक्त भोजन कराया गया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों व जनप्रतिनिधियों ने बच्चों के साथ पंगत में बैठकर भोजन किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

रचनात्मक प्रतियोगिताओं में बच्चों ने दिखाया हुनर

कार्यक्रम के दौरान विद्यालय में चित्रलेखन एवं भाषण प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए अपनी रचनात्मकता और उत्कृष्ट वक्तृत्व कला का प्रदर्शन किया। अतिथियों ने प्रतिभावान बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें शिक्षा के साथ-साथ अन्य सह-शैक्षणिक व रचनात्मक गतिविधियों में निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

जनभागीदारी से निर्मित होता है सकारात्मक वातावरण

समारोह को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन विद्यार्थियों में पोषण, शिक्षा, संस्कार और सामाजिक सहभागिता की भावना को मजबूत करते हैं। जनभागीदारी से आयोजित 'न्योता भोज' जैसे कार्यक्रम विद्यालयी माहौल को बेहतर बनाने के साथ-साथ बच्चों के बीच अपनत्व और सकारात्मकता का संचार करते हैं।

कार्यक्रम में इनकी रही गरिमामयी उपस्थिति इस अवसर पर जिला पंचायत सभापति श्रीमती नीलम राजेश चंद्राकर, मंडल अध्यक्ष कमलेश चंद्राकर, जनपद पंचायत सांसद प्रतिनिधि राजेश चंद्राकर, सरपंच एवं SMDC अध्यक्ष रवि सिंगौर, मंडल अध्यक्ष संजय सिंगौर, पंच शुभम जांगड़े, पंच महेंद्र पारधी, पंच तुलाराम सिंगौर, स्वच्छ अध्यक्ष एवं बूथ अध्यक्ष छोटू यादव, स्वच्छ उपाध्यक्ष ओमप्रकाश सिंगौर, बूथ अध्यक्ष कांता सिंगौर, कामता सिंगौर, विकाश सिंगौर, राजकुमार सिंगौर, लक्ष्मी सिंगौर सहित समस्त शिक्षकगण, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणजन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों एवं जनप्रतिनिधियों ने विद्यार्थियों के उत्तम स्वास्थ्य, निरंतर सफलता और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं व्यक्त कीं।

कृषि अधिकारी निलंबित : बिना सूचना लंबे समय से थे अनुपस्थित, किसानों से जुड़े काम प्रभावित होने की शिकायत

कोरबा। कटघोरा कृषि विभाग में पदस्थ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी देवशरण पैकरा को लंबे समय तक बिना सूचना और स्वीकृत अवकाश के कार्यक्षेत्र से अनुपस्थित रहने के मामले में निलंबित कर दिया गया है। उप संचालक कृषि, जिला कोरबा ने 15 सितंबर 2026 को निलंबन आदेश जारी किया है।

विभागीय आदेश के अनुसार, देवशरण पैकरा कटघोरा और जेंजरा क्षेत्र में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। आदेश में कहा गया है कि वे 1 अगस्त 2026 से बिना सूचना और स्वीकृत अवकाश के कार्यक्षेत्र से अनुपस्थित थे।

विभाग ने अधिकारी की अनुपस्थिति को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 का उल्लंघन माना है। विभागीय पत्राचार और अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रस्ताव के आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1) के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई है। निलंबन अवधि के दौरान देवशरण पैकरा का मुख्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखंड पोड़ी-उपरोड़ा कार्यालय निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

मामले के सामने आने के बाद भाजपा झुग्गी-झोपड़ी प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक राजेश यादव ने अधिकारी की लंबे समय तक अनुपस्थिति से किसानों से जुड़े कार्यों पर संभावित असर की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि कटघोरा और जेंजरा क्षेत्र में कृषि विभाग की योजनाओं, तकनीकी मार्गदर्शन और किसानों को मिलने वाली सेवाओं पर यदि अधिकारी की अनुपस्थिति का असर पड़ा है तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने क्षेत्र में तत्काल वैकल्पिक अधिकारी की व्यवस्था करने की मांग की है, ताकि किसानों को विभागीय योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी न हो।

राजेश यादव ने संबंधित अधिकारी पर महिला अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति कथित आपत्तिजनक एवं अभद्र टिप्पणियां किए जाने के आरोपों की भी निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका कहना है कि यदि विभागीय व्हाट्सएप ग्रुप में इस तरह की टिप्पणियां की गई हैं, तो संबंधित रिकॉर्ड की तथ्यात्मक जांच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि आरोप सही पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि इस रिपोर्ट में नहीं हुई है और इनकी वास्तविकता जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।

त्यौहारी सीजन के बीच सुनालिया पुल पर भारी वाहनों, बसों के परिचालन से लग रहा जाम

कोरबा। पावर हाउस रोड स्थित सुनालिया पुल और चैक के पास संकरी सड़क त्यौहारी सीजन गणेशोत्सव के बीच शहरवासियों का सिरदर्द बढ़ा रही है। गुणवताहीन मरम्मत कार्य की वजह से बरसात में पूरी तरह उखड़ चुकी सड़क में बजरी एवं गर्दा (धूल) उड़ने की वजह से राहगीर धूल फाँकने पर मजबूर हैं तो वहीं इस मार्ग में ट्रैक्टर,बसों के दिन में भी परिचालन की वजह से सुबह से शाम तक लग रही जाम से जनता हलाकान हो रही।

बुधवार को दोपहर 12.15 बजे करीब आधा घण्टे तक जाम लगा रहा। जिससे लोग खासकर दुपहिया वाहन चालक बेहद परेशान दिखे। एम्बुलेंस तक फंसी रही। आम जनता इन तमाम अव्यवस्थाओं के लिए स्थानीय निगम प्रशासन ,शासन को कोसते नजर आए। साथ ही लोगों ने हैरानी जताई कि जिला प्रशासन के जिम्मदार अधिकारियों के संज्ञान में यह अव्यवस्था कैसे नजर नहीं आ रही। पूर्व में जिला प्रशासन द्वारा इस मार्ग में त्यौहारी सीजन में भारी वाहनों के दिन में परिचालन पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। लेकिन इस बार अब तक इस तरह की जनहितकारी कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही। गणेशोत्सव से शुरू हुई त्यौहारी सीजन अब लगातार 2 माह तक जारी रहेगी। शारदीय नवरात्रि, दीपावली,देवउठनी एकादशी तक बाजार में रौनक रहती है। ऐसे में इस मार्ग आमजन को इन अव्यवस्थाओं से दो चार होना पड़ेगा। पुराने शहर की शुरुआत टीपी नगर के बाद सुनालिया पुल से पावर हाउस रोड के जरिए होती है। कोरबा का यह पूरा इलाका व्यापार का केंद्र बिंदु है. बड़ा थोक व्यापार यही से होता है। पूर्व सांसद, पूर्व महापौर से लेकर पूर्व मंत्री और वर्तमान महापौर का निवास भी पुराने शहर में है। ग्रामीण क्षेत्र से भी बड़ी तादात में लोग पुराने शहर आते हैं। रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए भी लोग इसी मार्ग का इस्तेमाल करते हैं। हर दिन बड़ी तादात में लोग यहां से सफर करते हैं।

पिछले कुछ सालों से इस स्थान पर जाम की समस्या इतनी विकराल हो गई है कि वाहनों के पहिए सुनालिया पुल पर पहुंचते पहुंचते थम जाते हैं। यातायात का दबाव तेजी से बढ़ा है. खासतौर पर सुबह के समय जब मार्केट खुलता है और शाम 5 बजे के बाद वाहनों की गति यहां धीमी हो जाती है। छुट्टी वाले दिन और त्योहारी सी तो लोग यहां घंटों फंस जाते हैं।

ड्यूटी में शराब और डायल 112 का एक्सीडेंट, आरक्षक सेवा से पृथक

वाड्रफनगर में सरकारी वाहन हुआ था क्षतिग्रस्त, विभागीय जांच के बाद एसपी ने की कार्रवाई

बलरामपुर (जनता के गोठ) : वाड्रफनगर क्षेत्र में ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में पाए गए आरक्षक संजय मारकण्डे (क्रमांक 878) को पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर ने 19 सितंबर को पुलिस सेवा से पृथक कर दिया। पुलिस के अनुसार, 7 जुलाई 2026 की रात डायल 112 वाहन क्रमांक छत्त-03ज़-2749 में आरक्षक संजय मारकण्डे और चालक ओमप्रकाश यादव घटना की सूचना पर ग्राम सिवरी बरतीकला जा रहे थे। इसी दौरान न्यू पंचवटी ढाबा के पास पिकअप UP-64-CT-1055 से डायल 112 वाहन की जोरदार टक्कर हो गई और सरकारी वाहन गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद दोनों का मेडिकल कराया गया। पुलिस के मुताबिक, मेडिकल रिपोर्ट में दोनों के शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई। विभागीय जांच में आरक्षक के विरुद्ध ड्यूटी के दौरान शराब सेवन, लापरवाही और गंभीर कदाचरण प्रमाणित पाए जाने पर एसपी ने उसे तत्काल प्रभाव से पुलिस सेवा से पृथक कर दिया।

मुर्गा बाजार के नाम पर कथित अवैध वसूली! 100 रुपये तक प्रवेश शुल्क,

क्षमापुर में मुर्गा लड़ाई देखने उमड़ रहा जनसैलाब, ओडिशा से भी पहुंच रहे लोग - प्रत्यक्षदर्शी

बकावंड जनता के गोठ7

विकासखंड बकावंड की ग्राम पंचायत क्षमापुर में आयोजित होने वाले कथित मुर्गा बाजार को लेकर ग्रामीणों और दर्शकों ने अवैध वसूली का आरोप लगाया है।

ग्रामीणों का कहना है कि मुर्गा लड़ाई देखने आने वालों से प्रवेश के नाम पर 100 रुपये तक की राशि कथित रूप से वसूली जा रही है। ग्रामीणों ने इस वसूली की वैधता, आयोजन की अनुमति और पंचायत स्तर पर हो रहे आर्थिक लेन-देन की जांच की मांग की है।

ग्रामीणों के अनुसार क्षमापुर में मुर्गा लड़ाई का आयोजन दो से तीन बार किया जाता है और यह कुछ लोगों के लिए कमाई का जरिया बन गया है। आरोप है कि बाजार परिसर में दर्शकों से प्रवेश के नाम पर जबरन राशि ली जाती है।

नहीं देने पर दुर्व्यवहार का आरोप

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कई दर्शक तत्काल शुल्क देने में असमर्थता जताते हुए बाद में पैसा देने की बात कहते हैं, लेकिन वसूली करने वाले इसे स्वीकार नहीं करते। आरोप है कि राशि नहीं देने पर दर्शकों के साथ गाली-गलौज, धक्का-मुक्की और दुर्व्यवहार कर उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है।

पंचायत से हिसाब सार्वजनिक करने की मांग

मुर्गा बाजार से वसूली जाने वाली राशि को लेकर भी सवाल उठे हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि पंचायत स्पष्ट करे कि बाजार से कुल कितनी राशि वसूली गई, कितनी राशि पंचायत खाते में जमा हुई और क्या वसूली की रसीद दी गई या नहीं।

ओडिशा कनेक्शन का भी आरोप

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ओडिशा में प्रतिबंध होने के कारण वहां से बड़ी संख्या में लोग मुर्गे लेकर क्षमापुर पहुंचते हैं और यहां लड़ाई कराई जाती है। ग्रामीणों ने इस दावे की भी प्रशासनिक जांच की मांग की है।

ग्रामीणों का कहना है कि यदि आयोजन नियमों के विपरीत है तो इसे तत्काल रोका जाए, और यदि अनुमति है तो उसकी शर्तें व शुल्क वसूली की व्यवस्था सार्वजनिक की जाए।

दुर्ग - समाज रत्न दाऊ साव की 47वीं पुण्यतिथि पर चीरपोटी में हुआ भव्य आयोजन

वरिष्ठजनों के योगदान को याद रखना और नई पीढ़ी को संस्कार देना ज़रूरी - ताम्रध्वज साहू

अंचल वर्मा - दुर्ग, उतई। जनता के गोठ।

उतई। आज शनिवार ग्राम चीरपोटी में शनिवार को 'समाज रत्न' पूज्य दाऊ उत्तम साव की 47वीं पुण्यतिथि हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर समाज सेवा की भावना को जीवंत रखते हुए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर एवं स्थानीय कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ स्व. दाऊ उत्तम साव के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलन एवं विविध पूजा-अर्चना के साथ हुआ। इसके बाद स्थानीय कलाकारों ने अपनी सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुति दिया । इस अवसर पर पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने स्व. उत्तम साव को नमन करते हुए कहा, ÷समाज को संगठित करने और इसे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने में हमारे पुराने सियानों और दाऊ उत्तम साव का बहुत बड़ा योगदान रहा है वर्तमान में समाज को पुनः उसी एकजुटता की आवश्यकता है। उन्होंने सामाजिक चेतना पर ज़ोर देते हुए कहा कि आज कई घरों में भक्त माता कर्मा की जीवनी के बारे में जानकारी का अभाव है। माता कर्मा का चित्र हर साहू समाज के घर में होना चाहिए। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यदि हम अपनी नई पीढ़ी को संस्कार और समाज के आयोजनों से नहीं जोड़ेंगे, तो आने वाले समय में सामाजिक संरचना को नुकसान पहुँच सकता है। बच्चों को बचपन से ही सामाजिक आयोजनों में लाएं, ताकि वे अपनी संस्कृति और दायित्वों को समझ सकें।

प्रदेश साहू संघ छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष डॉ. निरेंद्र साहू ने अपने संबोधन में दाऊ उत्तम साव के योगदान को याद करते हुए बताया कि जब छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू समाज का गठन हुआ था, तब सर्वसम्मति से दाऊ उत्तम साव को अध्यक्ष चुना गया था।

उन्होंने युवाओं की कम उपस्थिति पर चिंतन व्यक्त करते हुए कहा, आज समाज में शिक्षा का स्तर बढ़ाने और युवाओं को संस्कारी बनाने की सख्त ज़रूरत है। युवा वर्ग पढ़ाई-लिखाई में आगे आए, तभी समाज का भविष्य उज्ज्वल होगा ।आगामी कार्यक्रमों में युवाओं की शत- प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।÷

निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में सैकड़ों ग्रामीणों ने उठाया लाभ ।

दाऊ उत्तम साव के पुण्य स्मरण में महिमा हॉस्पिटल (उतई) के सहयोग से एक विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में डॉ. ललित साहू, डॉ. सिंधु साहू, करुणा, खिलेश, राधे साहू और रितेश साहू की टीम ने मरीजों की स्वास्थ्य जांच की और ज़रूरतमंदों को निःशुल्क दवाइयाँ वितरित कीं।

प्रमुख अतिथियों एवं सामाजिक प्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति

आयोजन में पूर्व कैबिनेट मंत्री रमशीला साहू, डॉ. दयाराम साहू, प्रदेश साहू संघ के महामंत्री राजेश साहू, जिला साहू संघ दुर्ग के अध्यक्ष नंदलाल साहू, दुर्ग ग्रामीण तहसील अध्यक्ष पी.आर. साहू, जिला पंचायत दुर्ग की सभापति श्रद्धा साहू, जनपद पंचायत दुर्ग के उपाध्यक्ष राकेश हिरवानी, जनपद सदस्य ढालेश साहू, ग्राम चीरपोटी की सरपंच पूजा चंद्राकर, परिक्षेत्र साहू संघ खोपली के अध्यक्ष घनश्याम गजपाल, सुभाष साव, नगर पंचायत उतई के पूर्व अध्यक्ष डीकेन्द्र हिरवानी, डॉ. पिलेश्वर साहू, कृष्ण कुमार साहू, जागेश्वर साहू, पोषण साहू, राधिका हिरवानी, जामवंत गजपाल, रूपेंद्र साहू ,भूषण साहू,सहित बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु एवं ग्रामीण जन उपस्थित रहे।

सेवा संकल्प से साकार हुआ मधु का सपना, पक्के आशियाने में विराजे गणेश

रायपुर, 20 सितम्बर 2026

सेवा संकल्प अभियान के तहत शासन की जनकल्याणकारी योजनाएं जरूरतमंद परिवारों के जीवन में सेवा की नई कहानी लिख रही हैं। रामानुजनगर जिला सूरजपुर निवासी श्रीमती मधु जायसवाल के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से मिला पक्का घर वर्षों के इंतजार के बाद साकार हुआ सपना है। नए आशियाने में भगवान गणेश की स्थापना के साथ परिवार की खुशियों को नया अर्थ मिला है।

कभी कच्चे मकान में रहने वाले श्रीमती मधु जायसवाल के परिवार के लिए बारिश का मौसम चिंता लेकर आता था। टपकती छत, घर में भरता पानी और घरेलू सामान को सुरक्षित रखने की चुनौती के बीच परिवार हर मौसम कठिनाइयों से गुजरता था। सीमित आर्थिक संसाधनों के कारण पक्का मकान बनाना वर्षों तक उनके लिए एक अधूरा सपना बना रहा।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास स्वीकृत होने के बाद परिवार के जीवन में बदलाव की शुरुआत हुई। शासन से मिली सहायता से उनका पक्का घर तैयार हुआ और परिवार को कच्चे मकान की परेशानियों से स्थायी राहत मिली। अब परिवार अपने सुरक्षित और सुविधाजनक आशियाने में सुकून के साथ जीवन बिता रहा है।

नए घर में प्रवेश के साथ परिवार ने भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की। श्रीमती मधु के लिए यह पल केवल पूजा-अर्चना का अवसर नहीं, बल्कि वर्षों के संघर्ष के बाद मिली सुरक्षा, सम्मान और खुशियों की नई शुरुआत का प्रतीक बन गया। गणेश स्थापना के साथ परिवार ने अपने नए घर में सुख-समृद्धि की कामना की।

श्रीमती मधु जायसवाल ने कहा कि पक्का घर उनके परिवार के लिए बहुत बड़ी खुशी है। वर्षों से जिस सुरक्षित आशियाने का सपना देखा था, वह आज पूरा हो गया है। अब बारिश में छत टपकने और घर में पानी भरने की चिंता नहीं रहती।

उपसरपंच सुमित्रा भद्रे ने कहा - स्टॉक रजिस्टर से लेकर निर्माण स्थल तक जांच हो

उपसरपंच ने उठाए सवाल— 300 बोरी सीमेंट का हिसाब नहीं, बिल-वाउचर से लेकर निर्माण स्थल तक जांच की मांग

बकावंड जनता के गोठ।

ग्राम पंचायत बकावंड में पंचायत निधि के कथित दुरुपयोग को लेकर उपसरपंच श्रीमती सुमित्रा भद्रे ने गंभीर सवाल उठाते हुए जांच की मांग की है। उनका आरोप है कि बिना वास्तविक निर्माण कार्य के सीमेंट खरीदी दर्शाकर पंचायत निधि से राशि का भुगतान किया गया है। उपसरपंच के अनुसार सामने आए एक बिल में डी.बी. ट्रेडर्स, बकावंड से दिनांक 3 अगस्त 2026 को 300 बोरी सीमेंट की खरीदी दर्शाई गई है। बिल में इसकी कुल राशि 93 हजार रुपये बताई गई है। श्रीमती भद्रे ने आरोप लगाया कि जिस फर्म के नाम से यह बिल जारी हुआ है, वह पंचायत सचिव के भाई की फर्म है। उन्होंने इसे संभावित हितों के टकराव का मामला बताते हुए पूरे भुगतान की जांच की मांग की है।

300 बोरी सीमेंट कहां उपयोग हुई?

उपसरपंच ने सवाल उठाया कि यदि पंचायत द्वारा वास्तव में 300 बोरी सीमेंट खरीदी गई है तो उसका उपयोग किस निर्माण कार्य में किया गया? सीमेंट किस स्थान पर पहुंचाई गई और किस कार्य में लगाई गई? उन्होंने स्टॉक रजिस्टर में दर्ज मात्रा, बिल-वाउचर, कैशबुक और बैंक भुगतान का मिलान कराने की मांग की है।

उन्होंने यह भी कहा कि संबंधित निर्माण कार्य का मौके पर भौतिक सत्यापन कराया जाना चाहिए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि खरीदी गई सामग्री वास्तव में पंचायत के कार्य में उपयोग हुई है या नहीं।

उच्चस्तरीय जांच की मांग

श्रीमती भद्रे ने संबंधित अधिकारियों से पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि जांच के दौरान बिल, वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कैशबुक, बैंक खाते से किए गए भुगतान तथा संबंधित निर्माण स्थल का भौतिक सत्यापन कराया जाए। यदि जांच में अनियमितता, फर्जी बिल अथवा नियमों के विपरीत हितों का टकराव सामने आता है तो जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।

उपसरपंच ने कहा कि पंचायत की राशि ग्रामीणों के विकास और सार्वजनिक कार्यों के लिए होती है। इसका उपयोग पारदर्शी तरीके से होना चाहिए तथा पंचायत निधि के खर्च का पूरा हिसाब जनता के सामने स्पष्ट रहना चाहिए।

जनदर्शन में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने सुनीं नागरिकों की समस्याएं, संबंधित अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश

रायपुर। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने आज अपने निज निवास, लखनपुर में आयोजित जनदर्शन के दौरान प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों से भेंट की। उन्होंने नागरिकों की समस्याओं, आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को गंभीरता से सुना तथा संबंधित विषयों पर आवश्यक जानकारी लेकर उनके निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए।

जनदर्शन में प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों ने विभिन्न व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक समस्याओं से मंत्री श्री अग्रवाल को अवगत कराया। नागरिकों ने अपने क्षेत्रों से जुड़ी आवश्यकताओं और विकास संबंधी विषयों को भी उनके समक्ष रखा। मंत्री श्री अग्रवाल ने प्रत्येक नागरिक की बात ध्यानपूर्वक सुनी और संबंधित विभागों एवं अधिकारियों से समन्वय कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

सेवा संकल्प अभियान का उद्देश्य जनसेवा, जनभागीदारी और समाज के विभिन्न वर्गों तक शासन की योजनाओं एवं सेवाओं की पहुंच को और प्रभावी बनाना है। इसी भावना के अनुरूप जनप्रतिनिधियों और नागरिकों के बीच सतत संवाद महत्वपूर्ण माध्यम है। जनदर्शन के माध्यम से नागरिकों को अपनी समस्याएं सीधे रखने और उनके समाधान की दिशा में आवश्यक कार्रवाई का अवसर मिल रहा है।

श्री अग्रवाल ने कहा कि जनसेवा के लिए नागरिकों से सीधा संवाद बेहद महत्वपूर्ण है। जनदर्शन के माध्यम से प्राप्त समस्याओं को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाकर उनके नियमानुसार निराकरण की दिशा में कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नागरिकों की अपेक्षाओं और सुझावों को सुनने तथा उनकी समस्याओं के समाधान के लिए संवाद का यह क्रम निरंतर जारी रहेगा।

निज निवास, लखनपुर में आयोजित जनदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। जनसुनवाई और जनसंवाद का यह क्रम नागरिकों की समस्याओं के समाधान तथा प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक समन्वय को मजबूत करने की दिशा में जारी रहेगा।

संपादकीय

कुकी समुदाय के 'काला दिवस' पर मणिपुर में हिंसा, क्या फिर तेज होगा जातीय संघर्ष?

कुकी समुदाय वर्ष 1990 के दशक में राज्य में कुकी-नगा संघर्ष के दौरान मारे गए लोगों की याद में हर साल 13 सितंबर को काला दिवस मनाता है। किसी भी सरकार की यह नीतिगत और नैतिक जिम्मेदारी होती है कि समाज में शांति एवं सौहार्द बना रहे। तभी आम लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। मगर, लंबे समय से जातीय हिंसा और सामाजिक तनाव से जूझ रहे मणिपुर में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। आए दिन हिंसक घटनाओं का राज्य की सामाजिक संरचना, अर्थव्यवस्था और जनजीवन पर गहरा असर पड़ रहा है।

हालांकि, हालात में कई बार सुधार के संकेत दिखाई दिए, लेकिन तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। पिछले कुछ समय से स्थिति फिर बिगड़ने लगी है। इसी का नतीजा है कि राज्य के तामेंगलोंग और नोनी जिलों में बीते रविवार को उग्रवादियों के हमलों में दो महिलाओं सहित चार लोगों की मौत हो गई। इस पर सरकार का कहना है कि निर्दोष नागरिकों के खिलाफ हिंसा पूरी तरह अस्वीकार्य है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।मगर, सवाल है कि अगर सरकार इस मसले पर इतनी गंभीर है और इससे निपटने के लिए जरूरी कदम उठा रही है, तो फिर धरातल पर उसका असर दिखाई क्यों नहीं दे रहा है?दरअसल, मणिपुर की समस्या केवल जातीय संघर्ष तक सीमित नहीं है। इसके पीछे प्रशासनिक व्यवस्था, रोजगार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और संसाधनों को लेकर समुदायों के बीच लंबे समय से चले आ रहे अविश्वास जैसे कई जटिल कारण भी हैं। इसलिए केवल सुरक्षा बलों की तैनाती या तनावग्रस्त इलाकों में प्रतिबंध लगाने से समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाएगा।हिंसा को रोकना जरूरी है, लेकिन उसके साथ उन कारणों को समझना और दूर करना भी आवश्यक है, जिनसे तनाव बार-बार पैदा होता है। हिंसा की ताजा घटनाएं कुकी समुदाय की ओर से मनाए जाने वाले 'काला दिवस' के मौके पर हुईं। यह समुदाय वर्ष 1990 के दशक में राज्य में कुकी-नगा संघर्ष के दौरान मारे गए लोगों की याद में हर साल 13 सितंबर को काला दिवस मनाता है।जाहिर है कि इस समुदाय के लोग उग्रवादियों के हमले को जातीय हिंसा से जोड़कर देख रहे हैं। कुकी-जो काउंसिल का कहना है कि सशस्त्र समूहों की गतिविधियां आम नागरिकों की जान पर भारी पड़ रही हैं और इससे राज्य में फिर से जातीय संघर्ष तेज होने का खतरा है।मणिपुर में विस्थापन भी एक गंभीर समस्या है। हिंसा के कारण बड़ी संख्या में लोग अपने घर छोड़कर लंबे समय से राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। इन लोगों की घर वापसी केवल प्रशासनिक आदेश से संभव नहीं होगी, उन्हें सुरक्षा का भरोसा, आजीविका के साधन और संपत्ति तथा पुनर्वास को लेकर ठोस उपायों की जरूरत है।

यूपीआइ का ढांचा भारत ने बनाया, लेकिन उसका सबसे बड़ा बाजार निजी कंपनियों के हाथ चला गया। फोनपे और गूगलपे मिलकर करीब अस्सी फीसद यूपीआइ लेन-देन संभालते हैं। फोनपे में अमेरिकी कंपनी वालमार्ट की बड़ी हिस्सेदारी है और गूगलपे अमेरिकी कंपनी अल्फाबेट का हिस्सा है। दूसरी ओर, नोटबंदी के बाद तेजी से बढ़ा पेटीएम कुछ ही वर्षों में बड़े निजी डिजिटल भुगतान कारोबार में बदला और 2021 में अपना आइपीओ लाकर वह सूचीबद्ध कंपनी बन गया। सवाल है कि जब डिजिटल भुगतान का आधार भारत ने बनाया, तो उसका बड़ा कारोबारी लाभ निजी और विदेशी पूंजी वाली कंपनियों के हिस्से में क्यों गया? सरकार ने 'भीम' ऐप बनाया, सार्वजनिक बैंकों के पास करोड़ों ग्राहक थे और एसबीआइ ने 'योनो' जैसा मंच खड़ा किया, फिर भी वह पीछे रह गया। एसबीआइ के अध्यक्ष सीएस शेट्टी ने खुद स्वीकार किया कि बैंक डिजिटल भुगतान की दौड़ में पीछे छूट गया है। जब ढांचा अपना था, ग्राहक अपने थे और बैंक अपने थे, तो अपने मंच पीछे और निजी मंच आगे कैसे हो गए?

84 फीसद डिजिटल पेमेंट में यूपीआई की हिस्सेदारी, क्या महंगा होगा भुगतान या बदल जाएगा कारोबारियों का व्यवहार?

(पीएस वोहरा)

अब तक आम धारणा यही रही कि यूपीआइ से भुगतान करना लगभग पूरी तरह निशुल्क है और यह व्यवस्था बनी रहेगी। मगर सरकार की नई व्यवस्था के बाद यह तस्वीर अब बदलने जा रही है। पंद्रह अक्तूबर 2026 से सभी व्यापारिक भुगतान पूरी तरह शुल्क मुक्त नहीं रहेंगे। हालांकि दो व्यक्तियों के बीच होने वाले भुगतान पर कोई शुल्क नहीं लगेगा और दो हजार रुपए तक के व्यापारिक भुगतान भी शुल्क मुक्त रहेंगे, लेकिन दो हजार रुपए से अधिक के कुछ व्यापारिक भुगतानों पर शुल्क लागू होगा।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह शुल्क ग्राहक से अलग से नहीं लिया जाएगा और इसे कर भी नहीं माना जाएगा। फिर भी इस फैसले ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि जिस यूपीआइ को देश में डिजिटल भुगतान की सबसे बड़ी सार्वजनिक आधारभूत व्यवस्था के रूप में खड़ा किया गया, उसकी लागत का बोझ अब किस तरह और किस पर पड़ेगा?

यूपीआइ उस बदलाव की कहानी है, जिसने भारत में भुगतान के तौर-तरीके को ही बदल दिया। अप्रैल 2016 में यूपीआइ की शुरुआत 21 बैंकों के साथ हुई थी। अगस्त 2016 में करीब नब्बे हजार रुपए के लेन-देन हुए। शुरुआत छोटी थी, लेकिन इसके बाद घटनाक्रम ने असाधारण गति पकड़ी। आठ नवंबर 2016 को पांच सौ और एक हजार रुपए के पुराने नोटों को चलन से बाहर करने की घोषणा हुई। इसके बाद नकदी की उपलब्धता अचानक सीमित हो गई और डिजिटल भुगतान के लिए एक विशाल नया बाजार तैयार हुआ।

पेटीएम जैसे डिजिटल भुगतान मंचों ने इस दौर में तेज वृद्धि दर्ज की। उसने उस समय अपने लेन-देन और उपयोगकर्ताओं में कई गुना बढ़ोतरी के दावे किए। यह वही दौर था, जब डिजिटल भुगतान केवल सुविधा का विकल्प नहीं रहा, बल्कि रोजमर्रा के आर्थिक व्यवहार का महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनने लगा।

यूपीआइ ने इसके बाद लगातार नई ऊंचाइयां छुईं। अक्तूबर 2019 में एक अरब से अधिक लेन-देन का आंकड़ा पार हुआ। फरवरी 2020 में लेन-देन करीब 1.32 अरब तक पहुंच गए। फिर कोरोना महामारी और देशव्यापी बंद ने लोगों के भुगतान व्यवहार को एक और बड़ा मोड़ दिया। अप्रैल 2020 में भी यूपीआइ पर करीब एक अरब लेन-देन हुए।

इसके बाद अक्तूबर 2020 में यह आंकड़ा दो अरब से ऊपर चला गया और दिसंबर 2020 में करीब 2.23 अरब लेन-देन दर्ज किए गए। वित्त वर्ष 2025 से 2026 में देश के कुल डिजिटल भुगतान लेन-देन में यूपीआइ की हिस्सेदारी करीब 84 फीसद तक पहुंच गई। जुलाई 2026 में ही यूपीआइ पर करीब 23.66 अरब लेन-देन हुए, जिनका कुल मूल्य लगभग 29.88 लाख करोड़ रुपए रहा।

यूपीआइ उपभोक्ता के लिए अभी लगभग मुफ्त है, लेकिन इसे चलाना मुफ्त नहीं है। इसके पीछे सर्वर, तकनीकी ढांचा, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने की व्यवस्था, बैंकिंग नेटवर्क, ग्राहक सहायता और लगातार बढ़ते लेन-देन को संभालने की क्षमता पर भारी खर्च होता है। संसदीय वित्त संबंधी समिति के सामने रखे गए आंकड़ों के अनुसार, यूपीआइ के संचालन की अनुमानित वार्षिक लागत करीब 20,700 करोड़ रुपए है, जबकि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए सरकार ने करीब दो हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

यूपीआइ का ढांचा भारत ने बनाया, लेकिन उसका सबसे बड़ा बाजार निजी कंपनियों के हाथ चला गया। फोनपे और गूगलपे मिलकर करीब अस्सी फीसद यूपीआइ लेन-देन संभालते हैं। फोनपे में अमेरिकी कंपनी वालमार्ट की बड़ी हिस्सेदारी है और गूगलपे अमेरिकी कंपनी अल्फाबेट का हिस्सा है। दूसरी ओर, नोटबंदी के बाद तेजी से बढ़ा पेटीएम कुछ ही वर्षों में बड़े निजी डिजिटल भुगतान कारोबार में बदला और 2021 में अपना आइपीओ लाकर वह सूचीबद्ध कंपनी बन गया। सवाल है कि जब डिजिटल भुगतान का आधार भारत ने बनाया, तो उसका बड़ा कारोबारी लाभ निजी और विदेशी पूंजी वाली कंपनियों के हिस्से में क्यों गया?

सरकार ने 'भीम' ऐप बनाया, सार्वजनिक बैंकों के पास करोड़ों ग्राहक थे और एसबीआइ ने 'योनो' जैसा मंच खड़ा किया, फिर भी वह पीछे रह गया। एसबीआइ के अध्यक्ष सीएस शेट्टी ने खुद स्वीकार किया कि बैंक डिजिटल भुगतान की दौड़ में पीछे छूट गया है। जब ढांचा अपना था, ग्राहक अपने थे और बैंक अपने थे, तो अपने मंच पीछे और निजी मंच आगे कैसे हो गए?

नई व्यवस्था में दो हजार रुपए तक के भुगतान और छोटे व्यापारियों के लिए शुल्क मुक्त व्यवस्था जारी रहेगी। सरकार के अनुसार, करीब 96 फीसद व्यापारिक लेन-देन इससे प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन दो हजार रुपए से अधिक के कुछ निर्धारित व्यापारिक भुगतानों पर 0.4 फीसद शुल्क लगेगा, जिसमें 75,000 रुपए या उससे अधिक के भुगतान पर अधिकतम तीन सौ रुपए की सीमा होगी।

कुछ निर्धारित क्षेत्रों में प्रति लेन-देन पांच रुपए तथा पूंजी बाजार से जुड़े भुगतान में 0.02 फीसद और अधिकतम तीन सौ रुपए तक का शुल्क प्रस्तावित है। व्यापारी यह शुल्क सीधे ग्राहक से अलग से नहीं वसूल सकते, लेकिन आर्थिक व्यवहार इतना सीधा नहीं होता। व्यापारी इस लागत को किसी दूसरी लागत में समायोजित कर सकता है या भविष्य में कीमतों को बदलने पर विचार कर सकता है।

हालांकि अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि इससे महंगाई बढ़ेगी, लेकिन यह सवाल जरूर है कि लगातार बढ़ती डिजिटल भुगतान लागत का अंतिम आर्थिक भार आखिर किसके हिस्से में जाएगा। इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या शुल्क लगने के बाद व्यापारी डिजिटल भुगतान को पहले जैसी सहजता से अपनाएंगे? यदि किसी भुगतान माध्यम को व्यापारी एक नियमित लागत के रूप में देखने लगे, तो क्या वे दूसरे भुगतान माध्यमों को प्राथमिकता देने की कोशिश नहीं करेंगे?

यही वह बिंदु है, जहां वर्ष 2016 की पूरी कहानी फिर सामने खड़ी हो जाती है। यूपीआइ ने ग्राहकों और व्यापारियों की अलग-अलग परेशानियों का एक ही समाधान दिया था। ग्राहक नकदी रखने की मजबूरी से बाहर आया और व्यापारी नकदी संभालने की मजबूरी से। ग्राहक के लिए खाते में मौजूद पैसा ही उसकी जेब बन गया और व्यापारी के लिए खाते में आने वाला भुगतान ही उसकी बिक्री की सुरक्षित प्राप्ति। एक रुपए से लेकर हजारों रुपए तक का लेन-देन कुछ ही क्षणों में पूरा होने लगा।

बैंकिंग शाखा, नकदी और खुले पैसों से जुड़ी अनेक रोजमर्रा की जटिलताएं पीछे छूट गईं, लेकिन अब पहली बार इस सहज व्यवस्था की लागत सामने आ रही है। डर यह नहीं कि ग्राहक से सीधे शुल्क लिया जाएगा। डर यह है कि व्यापारी के व्यवहार में बदलाव कहीं ग्राहक के व्यवहार को न बदल दे। बड़े कारोबारों के लिए यूपीआइ का महत्त्व छोटे व्यापारियों जैसा कभी नहीं रहा।

उनका भुगतान तंत्र पहले से ही औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था पर आधारित है। वेतन और मजदूरी का भुगतान बैंक खातों के माध्यम से, आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान बैंक हस्तांतरण या चेक से और बड़े कारोबारी लेन-देन भी बैंकिंग प्रणाली के निर्धारित माध्यमों से होते हैं। उनके लिए भुगतान की व्यवस्था किसी एक त्वरित भुगतान माध्यम पर निर्भर नहीं है।

असहमति का सम्मान जरूरी- संवाद, रिश्ते और लोकतंत्र की असली परीक्षा

(रामानुज पाठक)

मनुष्य ने सभ्यता इसलिए नहीं बनाई कि सब एक जैसा सोचें। सभ्यता का अर्थ है कि अलग-अलग सोच वाले लोग एक-दूसरे को नुकसान पहुंचाए बिना साथ रह सकें। मगर सभ्यता की इस लंबी यात्रा के बावजूद मनुष्य एक विकृत प्रवृत्ति से मुक्त नहीं हो पाया है। वह है- अपनी बात को विचार और दूसरे की बात को समस्या समझना। अपनी असहमति उसे स्वतंत्र चिंतन लगती है और दूसरे की असहमति अवज्ञा। ईर्ष्या और द्वेष की जड़ें इसी मानसिकता में छिपी हैं। यानी हम जो कहें- वह तुम सुनो, तुम जो कहो- उसे सुनना हमारी जिम्मेदारी नहीं। विडंबना यह है कि अधिकांश लोग सार्वजनिक जीवन में लोकतंत्र चाहते हैं, लेकिन अपने निजी संसार में मनमर्जी से काम करना चाहते हैं। राष्ट्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चाहिए, लेकिन परिवार में नहीं। समाज में समानता चाहिए, पर अपने संबंधों में नहीं। हम चाहते हैं कि बच्चे हमारी बात सुनें, लेकिन उनकी बात सुनने का धैर्य नहीं रखते। दूरियां किसी एक बड़े विवाद से नहीं बनतीं। वे छोटे-छोटे अनसुने वाक्यों से बनती हैं। किसी ने कुछ कहा और हमने पूरा सुने बिना उत्तर दे दिया। किसी ने असहमति जताई और हमने उसके चरित्र का फैसला सुना दिया। असली समस्या यह है कि हम सुनते हुए भी अपने भीतर बोलते रहते हैं। सामने वाला वाक्य पूरा नहीं करता और हमारे भीतर उत्तर तैयार हो जाता है। हम उसके शब्द नहीं सुन रहे होते, अपनी अगली प्रतिक्रिया लिख रहे होते हैं। मनुष्य को अपनी बात सही सिद्ध करने में कई बार अधिक आनंद आता है। वह बहस जीतकर लौटता है और मान लेता है कि संबंध भी जीत लिया। जबकि कई बार बहस में मिली विजय, संबंध में मिली पराजय होती है। आपने तर्क जीत लिया, लेकिन सामने वाले का मन खो दिया। यहीं से ईर्ष्या का दूसरा चेहरा सामने आता है। जब हम दूसरे की योग्यता स्वीकार नहीं कर पाते, तो उसकी उपलब्धि हमें अपनी कमी का आईना लगती है। वह आगे बढ़ता है और हमें लगता है कि हमारा स्थान पीछे हो गया। ईर्ष्या का सुविधाजनक रास्ता है उपलब्धि की व्याख्या बदल देना। मेहनत को भाग्य कह दीजिए, प्रतिभा को संयोग, उपलब्धि को सिफारिश और सफलता को कृपा कह दो। इससे आत्मसम्मान सुरक्षित रहता है। मगर असल बात यह है कि यदि सामने वाला सचमुच योग्य है, तो हमें अपने भीतर झांकना पड़ेगा। द्वेष इसी मानसिक सुविधा का अगला चरण है। ईर्ष्या पूछती है, इसके पास क्यों है? द्वेष कहता है, इसके पास नहीं होना चाहिए। फिर व्यक्ति दूसरे को गिराने में वही संतोष खोजने लगता है, जो उसे स्वयं ऊपर उठने में मिलना चाहिए था। विडंबना यह भी है कि दूर की सफलता हमें प्रेरित करती है और पास की सफलता परेशान। किसी अनजान व्यक्ति की उपलब्धि पर हम कहते हैं, देश का नाम रोशन कर रहा है। वही उपलब्धि पड़ोसी हासिल कर ले, तो भीतर का आलोचक जाग जाता है, इतनी भी बड़ी बात नहीं है। परिवार में यही मनोविज्ञान रिश्तों को भीतर से खोखला करता है। प्रेम के नाम पर अधिकार, संरक्षण के नाम पर नियंत्रण और अनुशासन के नाम पर भय पैदा किया जाता है। सामने वाले को इतना अपना मान लेते हैं कि उसकी स्वतंत्रता भूल जाते हैं। संबंधों का यह सबसे विचित्र विरोधाभास है कि जिसे हम अपना कहते हैं, उसी को सबसे कम स्वतंत्रता देना चाहते हैं। समाज में यही मानसिकता समूहवाद बन जाती है। हर समूह चाहता है कि उसकी आवाज सुनी जाए, लेकिन दूसरे की आवाज को शोर कहने में देर नहीं लगती। हर विचारधारा प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता चाहती है, मगर अपने भीतर प्रश्न उठाने वाले को संदेह की निगाह से देखती है। राष्ट्र का निर्माण केवल सीमाओं, संस्थाओं और कानूनों से नहीं होता, वह साझा मनोविज्ञान से भी बनता है। लोकतंत्र की असली परीक्षा तब नहीं होती, जब सब आप से सहमत हों। उसकी परीक्षा तब होती है, जब कोई असहमत होकर अपनी बात कह सके। सहमति में साथ चलना सुविधा है, असहमति में साथ रहना सभ्यता। हमें एक नया सामाजिक व्याकरण सीखना होगा, मैं सही हो सकता हूं, लेकिन केवल मैं ही सही हूं, यह जरूरी नहीं। किसी की बात सुन लेना उससे सहमत होना नहीं है। असहमति का सम्मान करना अपनी मान्यता छोड़ना नहीं है। जिसे अपने विचार पर विश्वास होता है, वह प्रश्न से नहीं डरता। प्रश्न विचार का शत्रु नहीं, उसकी अग्निपरीक्षा है। इसलिए परिवार में बच्चा प्रश्न पूछे, तो उसे चुप कराने के बजाय सुनिए। समाज में कोई असहमत हो, तो पहले यह समझिए कि वह किस अनुभव से बोल रहा है। किसी की सफलता दिखाई दे, तो उसमें अपनी पराजय मत खोजिए। सबसे कठिन प्रश्न यही है, क्या मैं सचमुच संवाद कर रहा हूं या केवल अपनी बात की स्वीकृति मांग रहा हूं? क्योंकि संवाद का उद्देश्य सामने वाले को हराना नहीं, समझना है।

संबंध का उद्देश्य दूसरे को अपने जैसा बनाना नहीं, उसके अलग होने की जगह बनाना है।

नरेन्द्र मोदी- दृढ़ संकल्प, सशक्त नेतृत्व, दूरदृष्टा और सर्वांगीण विकास के प्रेरणादायक प्रतीक

मोदी सरकार के कार्यकाल में देश की सीमाओं की रक्षा की बात करें तो आज देश के वीर योद्धाओं के हाथ दुश्मन पर कार्रवाई के लिए पूरी आजादी के साथ खुले हुए हैं, जिसकी बानगी देश व दुनिया के लोग नक्सल, आतंकियों, सर्जिकल स्ट्राइक व ऑपरेशन सिंदूर आदि में बखूबी देख चुके हैं, मां भारती के वीर सपूत अब बिना किसी दबाव के आतंकवादियों व नक्सलियों के जहरीले फन को निरंतर कुचल कर के सफाया करने का कार्य बखूबी कर रहे हैं।

(दीपक कुमार त्यागी)

भारत में लंबे समय तक लगातार केंद्र की सत्ता में रहने का कीर्तिमान बनाते हुए एक लोकप्रिय जननेता के रूप में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपनी राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानने की कार्यशैली के दम पर आधुनिक, सशक्त, शक्तिशाली नए भारत के एक ऐसे सफल शिल्पकार बन चुके हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आज विकास के पथ पर तेज़ी से अग्रसरित भारत, विकसित भारत बने के लिए सर्वांगीण विकास के कार्यों को धरातल पर मूर्त रूप देते हुए सफलता के नित-नए आयाम स्थापित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत में तेज़ी से आर्थिक सुधार हो रहे हैं, मोदी ने देश में परिवर्तन लाने के लिए शहर, कस्बों से लेकर के गांव, दुर्गम दूरदराज के इलाकों तक में भी अब विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे के अनवरत विकास का कार्य युद्ध स्तर पर चलवाने का कार्य कर रखा है। 21वीं सदी की आधुनिकता की दौड़ में एआई व डिजिटल क्रांति के क्षेत्र में भारत दुनिया भर में अपना लोहा मनवाने का कार्य कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विज़न के दम पर स्वदेशी को तेज़ी से बढ़ावा देकर के भारत तेज़ी से आत्मनिर्भर बनने का मुकाम हासिल कर रहा है। देश में विश्वस्तरीय आधुनिक सड़क, सागर व नभ मार्ग विकास के नित-नए मार्ग खोल रहे हैं। देश के पास विश्वस्तरीय अत्याधुनिक हथियारों के जखीरे व सुविधाओं से सुसज्जित ट्रैंड सेना का पूरा बड़ा लावा लश्कर मौजूद है, जो दुश्मन देशों से घिरे होने के बाद भी देश की सुरक्षा चिंताओं को दूर करने का कार्य बखूबी करता है। वैश्विक स्तर पर कूटनीति और देश की विभिन्न क्षेत्रों में मजबूत होती स्थिति के कारण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को आधुनिक भारत का शिल्पकार माना जाता है।

भारत में लंबे समय तक लगातार केंद्र की सत्ता में रहने का कीर्तिमान बनाते हुए एक लोकप्रिय जननेता के रूप में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपनी राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानने की कार्यशैली के दम पर आधुनिक, सशक्त, शक्तिशाली नए भारत के एक ऐसे सफल शिल्पकार बन चुके हैं, जिन्होंने आजादी के लगभग 7 दशकों का लंबा समय बीत जाने के बाद देश के दूरदराज, दुर्गम और सीमावर्ती इलाकों तक में भी विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का कार्य निरंतर शुरू कर रखा है, जो काबिले-तारीफ व अचंभित करने वाला है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में उनके कार्यकाल के दौरान देश में बड़े पैमाने पर धरातल पर नये भारत की परिकल्पना के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का कार्य तेज़ी से हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का यह प्रयास आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव तैयार करने का कार्य बखूबी कर रहा है। देश में आधुनिक रेलवे स्टेशन, बंदरगाह, सड़क, रोपवे, एक्सप्रेस-वे, नेशनल हाईवे आदि जगह-जगह बन रहे हैं। पूरे देश में सड़क, हवाई, रेल व जल मार्ग से यात्रा व माल ढुलाई आदि की व्यवस्था को बहुत तेज़ी से विश्वस्तरीय बनाया जा रहा है। प्रवासीनेटवर्क जुड़ें मोदी सरकार के कार्यकाल में देश की सीमाओं की रक्षा की बात करें तो आज देश के वीर योद्धाओं के हाथ दुश्मन पर कार्रवाई के लिए पूरी आजादी के साथ खुले हुए हैं, जिसकी बानगी देश व दुनिया के लोग नक्सल, आतंकियों, सर्जिकल स्ट्राइक व ऑपरेशन सिंदूर आदि में बखूबी देख चुके हैं, मां भारती के वीर सपूत अब बिना किसी दबाव के आतंकवादियों व नक्सलियों के जहरीले फन को निरंतर कुचल कर के सफाया करने का कार्य बखूबी कर रहे हैं। पिछले लगभग 4 या 5 दशक से आतंक की आग में झुलस रहे जम्मू-कश्मीर में अमन-चैन को कायम करने के लिए बड़े पैमाने पर कार्य किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप अब वहां पर शांति है। धारा 370 को हटाकर के जम्मू-कश्मीर के निवासियों को दशकों से वंचित किए गए उनके हक को वापस दिया गया। वहीं देशवासियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो जन धन योजना, कौशल भारत मिशन, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, सांसद आदर्श ग्राम योजना, श्रमेव जयते योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हृदय योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, उजाला योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री ज्योति ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, स्मार्ट सिटी योजना, अमृत योजना, डिजिटल इंडिया मिशन, स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना, उदय, स्टार्ट-अप इंडिया, सेतु भारतम योजना, स्टैंड अप इंडिया, ग्रामोदय से भारत उदय, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, नमामि गंगे योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान भारत योजना, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना आदि जैसी योजनाएं चल रही हैं। यह योजनाएं हम भारतवासियों के जीवन स्तर में सुधार करते हुए उसे बेहतर बनाने कार्य कर रही हैं।

अपनी दमदार कार्यशैली के दम पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जनता की अदालत में लोगों की आशा व उम्मीद का सकारात्मक प्रतीक बन चुकें हैं, लोग मान रहे हैं कि मोदी के नेतृत्व में भारत का बहुत तेज़ी से सर्वांगीण विकास हो रहा है। मोदी सनातन धर्म के गौरवशाली इतिहास को संरक्षित करते हुए देश व दुनिया को उससे बखूबी रूबरू करवा रहा है। आज का शक्तिशाली नया भारत आत्मनिर्भरता, विकास और वैश्विक सम्मान की एक नई ऊंचाइयों को छूने का कार्य कर रहा है। मोदी के नेतृत्व में विकासशील भारत अब विकसित भारत की दिशा में तेज़ी से आगे कदम बढ़ रहा है। जब पूरी दुनिया युद्ध व मंदी की मार से ग्रस्त हैं उस वक्त भी मोदी के प्रयासों से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और दुनिया के ताकतवर देशों को पीछे छोड़ने का कार्य कर रही है, जो एक बहुत अच्छा संकेत है। आज भारत दुनिया के निवेशकों की पसंदीदा जगह बनता जा रहा है, भारत में अब विदेशी कंपनियों के बड़े-बड़े कल-कारखाने खुलने लगें हैं। आर्थिक स्तर के मोर्चे के साथ-साथ सामरिक स्तर पर भी अब तो दुनिया भारत का लोहा मानने लगी है। आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ओजस्वी नेतृत्व में भारत विकास के नित-नए आयाम स्थापित करने का कार्य कर रहा है, लोग भी बढ़े ही आत्म विश्वास के साथ गर्व से कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। (लेखक अधिवक्ता, स्वतंत्र पत्रकार, स्तंभकार व राजनीतिक विश्लेषक है)। (इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

संक्षिप्त समाचार

जज अमोघ कलोती के पास है टाटा विवाद की चाबी

नई दिल्ली, एजेंसी। देश के सबसे बड़े औद्योगिक घराने टाटा ग्रुप में कोहराम मचा हुआ है। 125 अरब डॉलर के इस ग्रुप पर कंट्रोल को लेकर ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा संस और उसके सबसे बड़े शेयरहोल्डर टाटा ट्रस्ट्स आमने-सामने हैं। टाटा ग्रुप के इस विवाद की चाबी महाराष्ट्र के चैरिटी कमिश्नर अमोघ कलोती के पास है। कलोती ने ही मई 2026 में वेणु श्रीनिवासन की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए सर रतन टाटा ट्रस्ट को बोर्ड मीटिंग करने से रोका और उन ट्रस्टों के कामकाज की जांच का आदेश दिया। टाटा ट्रस्ट्स की टाटा संस में 66.4 प्रतिशत हिस्सेदारी है। टीओआई की

एक रिपोर्ट के मुताबिक अमोघ कलोती कानून और न्याय विभाग के तहत काम करते हैं। महाराष्ट्र के कानूनी हलकों के बाहर शायद ही किसी को उनके बारे में पता था। वह फरवरी 2024 में महाराष्ट्र के चैरिटी कमिश्नर नियुक्त किए गए और लो प्रोफाइल वाले जिला जज अब देश की सबसे हाई-प्रोफाइल कॉर्पोरेट लड़ाई में शामिल हो गए हैं। पेशे से वकील और अब नौकरशाह के तौर पर काम कर रहे 50 वर्षीय कलोती अमरावती के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई अमरावती से पूरी की और जिला एवं सत्र न्यायालय में वकील के तौर पर प्रैक्टिस की। वकील और जज दोनों ही भूमिकाओं में उन्हें शांत स्वभाव का, सोच-समझकर बोलने वाला और नियमों का सख्ती से पालन करने वाला माना जाता था। कलोती को 2013 में जिला और सहायक सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। उन्होंने बुलढाणा में जिला न्यायाधीश, मुंबई में सिटी सिविल और सत्र न्यायालय और छत्रपति संभाजीनगर में सत्र न्यायालय में काम किया। उन्हें वाशिम में प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में तैनात किया गया था। कलोती ने के कॉल और टेक्स्ट संदेशों का जवाब नहीं दिया।

पैसे लगाने की होड़, सिर्फ 6 महीने में 30 प्रतिशत तक का बंपर रिटर्न

नई दिल्ली, एजेंसी। पश्चिम एशिया में जारी तनाव, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और विदेशी निवेशकों की बिकवाली के बीच घरेलू शेयर बाजार ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। इस दौरान लोगों ने अपना रुख म्यूचुअल फंड की ओर की है। हाल ही में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी कि अगस्त 2026 के लिए आए डेटा ने एक बड़ी जानकारी दी थी। आंकड़ों में बताया गया था कि अगस्त में म्यूचुअल फंड की 11 सब-कैटेगरी में से सबसे अधिक पैसा 7973 करोड़ रुपये में लगाया गया है। मतलब कि इसमें पैसे लगाने के लिए निवेशकों की होड़ देखी गई। इन आंकड़ों के बाद से निवेशकों की नजर स्मॉल कैप फंड्स की एसआईपी पर ज्यादा दिख रही है। इस बीच हम यहां कुल 4 ऐसे इक्विटी स्मॉल कैप फंड्स की बात कर रहे हैं, जिन्होंने सिर्फ 6 महीने में 20 फीसदी से लेकर के 30 फीसदी तक का रिटर्न दिया है। आइए इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बंधन स्मॉल कैप फंड की बात करेंगे। यह इक्विटी स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड है। आंकड़ों के अनुसार, इसने बीते 6 महीने में अपने पात्र निवेशकों को 23.7 फीसदी का रिटर्न दिया है। अब बात इनवेस्को इंडिया स्मॉल कैप की। इसने बीते 6 महीने में अपने निवेशकों को 25 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ने बीते 6 महीने में 20.3 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। अब बात क्वांट स्मॉल कैप फंड की। इसने अपने पात्र निवेशकों की बंपर कमाई कराई है। बीते 6 महीने में क्वांट स्मॉल कैप से निवेशकों को 30.6 प्रतिशत का बंपर रिटर्न मिला है। उदाहरण से समझिए, किसी ने 10 हजार रुपये की हर महीने की एसआईपी 6 महीने तक की है और उसको इसपर 30.6 फीसदी का रिटर्न मिलता है। इस हिसाब से उसका कुल रिटर्न मेच्योरिटी सहित करीब 65,500 रुपये से अधिक होगा। इसमें उसे 5500 से अधिक का लाभ मिलेगा।

क्रूड ऑयल और गैस निकालने वाली आयल इंडिया अब 'गोबर गैस' भी बनाएगी

नोएडा, एजेंसी। ऑयल सेक्टर की महारत्न कंपनी का नाम तो सुना ही होगा। यह केंद्रीय पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस मिनिस्ट्री के तहत काम करती है। कंपनी ने ऑयल एवं गैस सेक्टर में अपनी भागीदारी बढ़ाने के लिए बड़ी योजना बनाई है। साथ ही ग्रीन एनर्जी की दिशा में भी बड़ा कदम उठा रही है। कंपनी ने देश भर में कम से कम 25 सीबीजी प्लांट लगाने का फैसला किया है। इनमें से दो प्लांट दिल्ली में एवं 4 प्लांट हरियाणा में लगेंगे। ऑयल इंडिया लिमिटेड का गुरुवार को 67वीं आम बैठक थी। इस दौरान कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक रणजीत रथ ने शेयरहोल्डर्स को अगले तीन साल के दौरान होने वाले निवेश की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कंपनी अगले तीन वर्षों के दौरान देश में ऑफशोर डीप और अल्ट्रा-डीप ब्लॉकों की खोज में करीब 15,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इस समय कंपनी कई ऑनशोर और ऑफशोर सेडिमेंटरी बेसिन्स में काम कर रही है। इसका ऑफशोर पोर्टफोलियो अब अंडमान, कृष्णा-गोदावरी, महानदी और केरल-कोंकण बेसिन्स में फैला है। इनमें अल्ट्रा-डीपवाटर ब्लॉक भी शामिल हैं, जहां सतह से 6,000 मीटर नीचे से ऑयल निकाला जाता है।

शेयर का क्या है भाव शुक्रवार को बीएसई सेंसेक्स सुबह करीब 300 अंक बढ़ कर खुला था। ऑयल इंडिया के शेयर भी सुबह बढ़ कर खुले थे। लेकिन यह बढ़त बरकरार नहीं रह सकी। गुरुवार को इसके शेयर बीएसई में 477 रुपये पर बंद हुए थे। शुक्रवार की सुबह यह बढ़ कर 478.95 रुपये पर खुले लेकिन बिकवाली क बीच यह 473.50 रुपये तक टूट गए। दिन में 10:48 बजे यह 2.65 रुपये गिर कर 474.35 रुपये पर ट्रेड हो रहे थे।

25 सीबीजी प्लांट लग रहे हैं

उन्होंने बताया कि इसी योजना के तहत 25 सीबीजी प्लांट लगाए जा रहे हैं। रथ ने बताया कि हर प्लांट में 150 से 180 करोड़ रुपये का निवेश होगा। इनमें से 7-8 प्लांट ओडिशा में, 5 प्लांट असम में, 4 प्लांट हरियाणा में और 2 कम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट दिल्ली में बन रहे हैं। उन्होंने बताया कि इनमें से दो प्लांट तो काफी एडवांस लेवल पर पहुंच गए हैं। शीघ्र ही इसे चालू कर दिया जाएगा। दिल्ली में जो दो सीबीजी प्लांट लगाने का मन बनाया है, उसके लिए फीडस्टॉक म्यूनिसिपल वेस्ट होगा। रथ ने बताया कि दिल्ली के प्लांट के लिए म्यूनिसिपल वेस्ट के लिए दिल्ली नगर निगम से करार किया गया है। साथ ही पड़ोसी राज्य हरियाणा के फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार और अंबाला/कुरुक्षेत्र में एक-एक प्लांट लगाने की योजना है। सीबीजी प्लांट में हर रोज करीब 1500 टन म्यूनिसिपल वेस्ट की आवश्यकता होगी। इसलिए पहले से करार किया जा रहा है। रथ ने बताया कि कंपनी साल 2040 तक नेट-जीरो कार्बन एमिशन कंपनी बनने का लक्ष्य रखा है। इसे हासिल करने के अपने विज़न के हिस्से के रूप में, कंपनी ने कहा कि वह ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के माध्यम से अपने क्लीन-एनर्जी पोर्टफोलियो का निर्माण कर रही है। इनमें जिसमें कम्प्रेस्ड बायोगैस इंटीग्रेटेड और वेस्ट-टू-एनर्जी प्रोजेक्ट्स, नवीकरणीय ऊर्जा और अन्य लो-कार्बन अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

यूपीआई पर चार्ज लगाने के पक्ष में आई भारत पे

विपक्षी पार्टियां, व्यापारी संघ और रिटेलर्स इसका विरोध कर रहे हैं

नई दिल्ली, एजेंसी। यूपीआई पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगाने के सरकार के फैसले पर घमासान मचा हुआ है। विपक्षी पार्टियां, व्यापारी संघ और रिटेलर्स इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि यह फैसला किसी भी सूरत में वापस नहीं लिया जाएगा। सरकार का तर्क है कि यह कोई टैक्स नहीं है, बल्कि यूपीआई इकोसिस्टम को टिकाऊ बनाने का माध्यम है। यह चार्ज केवल मर्चेंट्स पर है और ग्राहकों से किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाएगा।

इस बीच देश की सबसे बड़ी फिनटेक कंपनियों में से एक ने भी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के फ्रेमवर्क का समर्थन किया है। कंपनी का कहना है कि इस कदम से एक मजबूत और सस्टेनेबल पेमेंट इकोसिस्टम बनेगा।

क्या होगा फायदा

नलिन नेगी ने कहा, 'नया फ्रेमवर्क साबित करता है कि ग्राहकों के लिए फ्री बना रहेगा। साथ ही एक सस्टेनेबल, मजबूत और बेहतर पेमेंट इकोसिस्टम भी बनेगा। ग्राहक पेमेंट के लिए कोई चार्ज नहीं देंगे। साथ ही फ्रेमवर्क के तहत छोटे और माइक्रो मर्चेंट जीरो के साथ सुरक्षित रहेंगे।' नेगी ने के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि लगभग 96 प्रतिशत पर्सन-टू-मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमेशा से छोटे व्यापारियों का समर्थक रहा है और हम इस नजरिए का पुरजोर समर्थन करते हैं जो उन्हें सुरक्षित रखता है और साथ ही उस इकोसिस्टम को भी मजबूत करता है जिस पर वे निर्भर हैं। नया फ्रेमवर्क साबित करता है कि ग्राहकों के लिए फ्री बना रहेगा। साथ ही एक सस्टेनेबल, मजबूत और बेहतर पेमेंट इकोसिस्टम भी बनेगा। ग्राहक पेमेंट के लिए कोई चार्ज नहीं देंगे।

कंपनी की सफाई

प्रवक्ता ने कहा, 'ग्रोवर का 2024 से कोई संबंध नहीं है और वे न तो शेयरहोल्डर हैं और न ही किसी भी तरह से कंपनी से जुड़े हैं। इसलिए ग्रोवर के किसी भी बयान या विचार को कंपनी से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। फ्रेमवर्क और डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम पर हमारी राय हमारी मौजूदा लीडरशिप और अधिकृत प्रवक्ताओं द्वारा ही रखी जाती है।' हालांकि कंपनी के को-फाउंडर और पूर्व सीइओ अश्नीर ग्रोवर ने इसकी कड़ी आलोचना करते हुए दावा किया है कि इसका बोझ आखिरकार ग्राहकों पर ही पड़ेगा।

मुख्य रूप से फिजिकल स्टोर वाले व्यापारियों के लिए त्तक्र कोड-आधारित पेमेंट सॉल्यूशन और फाइनेंशियल सर्विस पर ध्यान केंद्रित करता है। इसकी स्थापना 2018 में अश्नीर ग्रोवर और शाश्वत नकरानी ने की थी। अश्नीर ग्रोवर ने 2022 में कंपनी छोड़ दी थी जबकि नकरानी ने भी इसी साल भारतपे के सीओओ पद से इस्तीफा दिया था। अश्नीर ग्रोवर ने 2,000 से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर एमडीआर लगाने के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने तर्क दिया कि पेमेंट पर लगाए जाने वाले किसी भी शुल्क को साफ तौर पर 'टैक्स' कहा जाना चाहिए। हालांकि भारतपे ने यह साफ किया कि एमडीआर पर ग्रोवर के विचार कंपनी की राय नहीं है। साथ ही फ्रेमवर्क के तहत छोटे और माइक्रो मर्चेंट जीरो के साथ सुरक्षित रहेंगे।

कम पैसे पर बड़ा फायदा! 3 करोड़ रुपये का टर्म इंश्योरेंस

नई दिल्ली, एजेंसी। देश की कई सारी बीमा कंपनियां कई प्रकार की बीमा सुविधा देती हैं। मेडिकल इंश्योरेंस से लेकर लाइफ इंश्योरेंस तक, वाहनों के बीमा से लेकर पूरे परिवार के बीमा तक। इस दौरान लोग सस्ते प्रीमियम में बंपर पैसे वाले बीमा की ओर रुख अधिक करते हैं। इस बीच हम 3 करोड़ रुपये के टर्म इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। टर्म इंश्योरेंस जिसमें कम प्रीमियम पर अच्छा-खासा पैसा या जीवन बीमा कवर की सुविधा मिलती है। यह बीमा एक शुद्ध जीवन बीमा प्लान है। टर्म इंश्योरेंस में बीमित व्यक्ति की मृत्यु के बाद बीमा की पूरी राशि उसके नॉमिनी को दे दी जाती है। आइए अब जानते हैं कि 3 करोड़ रुपये के बीमा के लिए कौन सा प्लान है और हर महीने आपको कितने रुपये का प्रीमियम भरना होगा। इंश्योरेंस पर लगने वाले मासिक प्रीमियम की बात करेंगे। इसके लिए हम प्लान के बारे में जानेंगे। पीएनबी मेटलाइफ देश की एक इंश्योरेंस कंपनी है। यह कई प्रकार की बीमा सुविधा देती है। इनमें से एक सुविधा 3 करोड़ रुपये के टर्म इंश्योरेंस की भी है। कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, आप जितनी जल्दी यानी कि कम उम्र में बीमा लेते हैं, उतना ही कम आपको प्रीमियम भरना होता है।

उदाहरण के लिए, अगर आप 25 वर्ष की उम्र में 3 करोड़ रुपये का टर्म इंश्योरेंस कराते हैं तो इसके लिए आपको हर महीने 1200 रुपये का प्रीमियम देना होता है। मतलब कि कंपनी के इस 3 करोड़ रुपये के टर्म इंश्योरेंस के प्रीमियम की शुरुआत 1200 रुपये से होती है। सभी बातें कंपनी की नियम और शर्तों के साथ आपकी पात्रता पर निर्भर करती हैं।

देश को विकसित अर्थव्यवस्था, हर भारतीय के जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं पीएम

नईदिल्ली, एजेंसी। मुझे लगने लगा था कि भारत का अपना पहला ग्रीन-फील्ड शहर बनाने का सपना शायद ही सच हो पाए। उस समय मैं दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर विकास कॉरपोरेशन का सीईओ था और मुझे भारत के औद्योगिक शहरीकरण के अगले चरण को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हर मुख्यमंत्री ने हमारे प्रस्ताव को यह कहकर ठुकरा दिया था कि ऐसी परियोजना के लिए 150 वर्ग किमी जमीन तय करना बहुत जोखिम भरा और मुश्किल काम है। फिर मैं गुजरात के सीएम ऑफिस पहुंचा। तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी ने मेरी बात सुनी, पांच मिनट तक सोचा और फिर बोले, '150 वर्ग किमी तो बहुत कम है। सपना देखना है, तो बड़ा देखो।'

उन्होंने 750 वर्ग किमी जमीन देने की पेशकश की। 2009 तक गुजरात सरकार ने विशेष निवेश क्षेत्र एक्ट लागू कर दिया और मास्टर प्लान के साथ धोलेरा की आधिकारिक घोषणा कर दी। उस पहली बातचीत से मुझे उनकी सोच के दायरे का पता चला। वह गुजरात और समय के साथ पूरे भारत के लिए विकास का एक नया इंजन बनाने की संभावना देख रहे थे। मेरे करियर में मिले वह सबसे दूरदर्शी और भविष्य की सोच रखने

वाले नेताओं में से एक हैं।

इसके कुछ समय बाद मैंने दो वाइब्रेंट गुजरात समिट में हिस्सा लिया और एक विकसित, गतिशील और विश्व-स्तरीय राज्य बनाने के लिए उनके जबरदस्त जुनून को देखा। वह चाहते थे कि गुजरात भारत का सबसे आधुनिक राज्य बने। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तो औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) के सचिव के तौर पर मैं उन शुरुआती अधिकारियों में से एक था, जिन्होंने उनके सामने प्रेजेंटेशन दिया। विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत को 142वें स्थान पर देखकर वह काफी निराश हुए। उन्होंने हमसे एक ही मिशन पर ध्यान देने को कहा- भारत को अपने नागरिकों और व्यवसायों के लिए ज्यादा आसान, सरल और बेहतर बनाना। इस तरह अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों में कड़ी मेहनत का दौर शुरू हुआ। हमने इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, जीएसटी पर काम किया और पुराने नियमों, कानूनों, प्रक्रियाओं व अधिनियमों को हटाने पर भी फोकस किया। आखिरकार, भारत रैंकिंग में 79 स्थान ऊपर आ गया।

इसके कुछ ही वक्त बाद हमने मेक इन इंडिया पर प्रधानमंत्री के सामने कई प्रस्तुतिकरण दिए। उन्हें पूरा भरोसा था कि अगर भारत को विनिर्माण के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो उसे रोजगार पैदा करना होगा, खुशहाली लानी होगी और तेजी से विकास करना होगा। मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर ऑटोमोबाइल, ईवी, दवाओं, रक्षा उपकरण, सोलर मॉड्यूल, टेलिकॉम और इंजीनियरिंग के सामानों तक- आज यह सोच कई क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विनिर्माण क्षमता के रूप में फैल चुकी है। पीएम मोदी युवा भारतीयों को उद्यमी बनाने के लिए भी उतने ही दृढ़ हैं। जब स्टार्टअप इंडिया अभियान शुरू हुआ, तो भारत में केवल 356 मान्यता प्राप्त स्टार्टअप थे। आज यह संख्या तीन लाख से ज्यादा हो चुकी है।

पीएम मोदी के लिए संभावनाओं की कोई सीमा नहीं। वह तकनीक की गहरी समझ रखने वाले नेताओं में से एक हैं। ऐसी नीतियां बनाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जिससे भारतीय उद्यमी आगे बढ़ सकें।

दोस्त का इंटरव्यू दिलाने गए थे, नौकरी खुद को मिल गई

नई दिल्ली, एजेंसी। 3000 रुपये की नौकरी, किंडरगार्टन का छोटा कमरा और फिर हजारों करोड़ की कंपनी... यह कहानी है पीयूष सोमानी की, जिन्होंने बेहद साधारण शुरुआत के बावजूद टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई। एक समय पीयूष अपने दोस्त को जॉब का इंटरव्यू दिलाने गए थे, लेकिन खुद को नौकरी मिल गई। बाद में उन्होंने बिजनेस की दुनिया में कदम रखा। उनकी कंपनी हाल ही में शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है। इस समय कंपनी का मार्केट कैप 19000 करोड़ रुपये से ज्यादा का हो गया है।

किंडरगार्टन में बना पहला ऑफिस

साल 2004 में जब पीयूष सोमानी ने अपना कारोबार शुरू किया, तब उनके पास न बड़ा ऑफिस था और न ही कोई बड़ा निवेशक। शुरुआत एक कंप्यूटर, बेसिक इंटरनेट कनेक्शन और टेक्नोलॉजी बिजनेस बनाने के भरोसे से हुई।

डेटा सेंटर में बड़ा दांव

साल 2008 में सोमानी ने नासिक के सतपुर इंडस्ट्रियल एरिया में करीब एक एकड़ जमीन खरीदी और अपना डेटा सेंटर बनाने का फैसला किया। उस समय यह फैसला काफी बड़ा दांव था। लेकिन 2010 में डेटा सेंटर शुरू हो गया। इसके बाद ने क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा सेंटर, मैनेज्ड सर्विसेज और सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने पर फोकस बढ़ाया।

472 करोड़ रुपये पहुंचा रेवेन्यू : कारोबार में पिछले कुछ वर्षों में तेजी आई है। वित्त वर्ष 2026 में कंपनी का ऑपरेशंस से रेवेन्यू 30.7 प्रतिशत बढ़कर 472.2 करोड़ रुपये पहुंच गया, जो वित्त वर्ष 2025 में 361.3 करोड़ रुपये था। इसी अवधि में कंपनी का मुनाफा 55.6 करोड़ रुपये से बढ़कर 120.8 करोड़ रुपये हो गया। शेयर बाजार में लिस्टिंग के बाद कंपनी के मार्केट कैप में भी बड़ा उछाल आया। बीएसई के आंकड़ों के मुताबिक, कंपनी का मार्केट कैप करीब 19,064 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है।

कभी नासिक के एक किंडरगार्टन के छोटे से कमरे में सात दोस्तों के साथ काम शुरू करने वाली इएसडीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन आज क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा सेंटर और एआइ इंफ्रास्ट्रक्चर के कारोबार में पहुंच चुकी है। वह इस कंपनी के एमडी और चेयरमैन हैं। शेयर बाजार में लिस्टिंग के बाद कंपनी की वैल्यूएशन में भी बड़ा उछाल देखने को मिला है। नासिक के कॉलेज रोड स्थित एक किंडरगार्टन के छोटे से कमरे को शुरुआती ऑफिस बनाया गया। दिन में जहां बच्चों की क्लास चलती थी।

दोस्त की जगह खुद को मिल गई नौकरी

पीयूष सोमानी की राह शुरुआत से आसान नहीं थी। साल 1997 में उन्होंने पुणे यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लेने की कोशिश की, लेकिन सीटों की कमी के कारण उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जाना पड़ा। उन्हें यह बदलाव पसंद नहीं आया और वह पहले साल में फेल भी हो गए। बाद में पिता की सलाह पर उन्होंने कंप्यूटर से जुड़ा 15 दिन का कोर्स किया। इस छोटे से कोर्स ने टेक्नोलॉजी के प्रति उनकी सोच बदल दी। इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद उन्होंने मुंबई में नौकरी की, जहां उनकी शुरुआती सैलरी सिर्फ 3,000 रुपये महीना थी। लेकिन नौकरी उन्हें ज्यादा समय तक रोक नहीं पाई। वह नासिक लौट आए। इसी दौरान एक दोस्त के साथ नौकरी के इंटरव्यू में पहुंचे। इंटरव्यू उनके दोस्त का था, लेकिन कंपनी के मालिक को सोमानी की बातचीत पसंद आ गई और नौकरी उन्हें मिल गई। नौकरी के अनुभव के बाद सोमानी ने अपना कारोबार शुरू करने का फैसला किया। साल 2004 में सात दोस्तों के साथ वेब-होस्टिंग और सपोर्ट बिजनेस शुरू किया गया। जनवरी 2005 में कंपनी को आधिकारिक तौर पर नाम से रजिस्टर किया गया। कारोबार बढ़ने के साथ कंपनी ने ब्रिटेन और अमेरिका में अधिग्रहण के जरिए भी विस्तार किया। हालांकि, शुरुआती सात साझेदारों के बीच समय के साथ मतभेद हुए और बाकी पार्टनर कंपनी से अलग हो गए। इसके बाद कारोबार की जिम्मेदारी मुख्य रूप से सोमानी के कंधों पर आ गई।

आईफोन 18 की बिक्री शुरू, स्टोर्स पर रात से ही लग गई लाइनें

नई दिल्ली, एजेंसी। अमेरिका की दिग्गज टेक कंपनी के लेटेस्ट आईफोन 18 और बिक्री आज से शुरू हो गई है। कंपनी के भारत में छह स्टोर हैं। इनमें मुंबई में दो और दिल्ली, नोएडा, बेंगलुरु और पुणे में एक-एक स्टोर

है। कल रात से ही लोग इनके बाहर जुटने शुरू हो गए थे। दुनियाभर में इनकी इतनी डिमांड है कि भारत में आईफोन की दो फैक्ट्रियां चौबीसों घंटे काम कर रही है। हालांकि श्चश्चद्द का पहला फोल्डेबल फोन ष्ठह्व भारत में नहीं बनाया जा रहा है। दिल्ली, मुंबई, नोएडा और बेंगलुरु में ऐपल के स्टोर्स के बाहर काफी भीड़ देखी गई। एएनआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक कस्टमर हितेश पटेल ने कहा, 'मैं नासिक से यहां आया हूं। हम कल रात 10 बजे से लाइन में लगे हुए हैं। मुझे सुबह 8 बजे का पहला स्लॉट मिला है। इसके बाद, हमें अपना प्रोडक्ट मिल जाएगा। मैं हर साल मोबाइल बदलता हूं। अभी मेरे पास 17 है, और अब मैं 18 लेने जा रहा हूं।' सूत्रों के मुताबिक भारत में बिकने वाले में से सिर्फ 15 प्रतिशत ही रेंज के होते हैं, इसलिए भारत में इनके प्रोडक्शन का लगभग 80-90 प्रतिशत हिस्सा विदेशों में भेजा जाएगा। यह पहली बार है जब कोई कंज्यूमर या बेस वर्जन लॉन्च नहीं किया है। माना जा रहा है कि अगले साल की पहली तिमाही में 18 आ सकता है। भारत में बिकने वाले में बेस मॉडल की हिस्सेदारी 80-85 प्रतिशत होती है।

संक्षिप्त समाचार

हैदराबाद में एनएच-44 पर भीषण सड़क हादसा : गणेश विसर्जन से लौट रहे 4 लोगों की दर्दनाक मौत, इनोवा चालक की हालत नाजुक

हैदराबाद , एजेंसी। राष्ट्रीय राजमार्ग-44 (एनएच-44) पर पलामकुला गांव के बाहरी इलाके में एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में इनोवा कार सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित अपने पैतृक गांव महबूबनगर में गणेश विसर्जन उत्सव में शामिल होने के बाद हैदराबाद लौट रहे थे, तभी यह भीषण हादसा हुआ। गणेश विसर्जन से लौटते समय हुआ हादसा शमशाबाद पुलिस के अनुसार, कार सवार सभी लोग महबूबनगर में गणेश प्रतिमा विसर्जन के धार्मिक अनुष्ठान को पूरा कर खुशी-खुशी घर लौट रहे थे। पलामकुला के पास तेज रफ्तार इनोवा अनियंत्रित होकर भीषण हादसे का शिकार हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार चार लोगों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। चालक की हालत गंभीर: दुर्घटना में इनोवा के चालक सबावत अशोक को गंभीर चोटें आई हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें तत्काल शमशाबाद स्थित ट्राइडेंट अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका गहन उपचार जारी है।शवों को भेजा गया मोर्चरी: पुलिस ने चारों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है और परिजनों को सूचित कर दिया गया है।

यूपी: मायावती का यू-टर्न, कांशीराम की जयंती पर पार्टी नहीं करेगी शक्ति प्रदर्शन; नहीं होगा सुप्रीमो का भाषण

लखनऊ , एजेंसी। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम के आगामी 9 अक्तूबर को परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर राजधानी में बसपा समर्थकों का हुजूम तो उमड़ेगा, लेकिन उन्हें पार्टी अध्यक्ष मायावती बीते वर्ष की तरह संबोधित नहीं करेंगी। सूत्रों के मुताबिक इस बार मायावती दिल्ली स्थित प्रेरणा स्थल में कांशीराम को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। उनकी अनुपस्थिति में बसपा के बड़े प्रदेश पदाधिकारियों के नेतृत्व में राजधानी में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बीते वर्ष कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर बसपा सुप्रीमो ने पुरानी जेल रोड स्थित कांशीराम स्मारक स्थल पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया था जिसमें लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी थी। विधानसभा चुनाव से करीब डेढ़ साल पहले हुए इस शक्ति प्रदर्शन से बसपा को खासा जनसमर्थन मिला था। इस बार मायावती ने कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर पूरे प्रदेश से कार्यकर्ताओं व समर्थकों को राजधानी आने को कहा है। हर बार यह कार्यक्रम लखनऊ और नोएडा में होता रहा है लेकिन नोएडा में कार्यक्रम स्थल पर मरम्मत का कार्य जारी होने की वजह से दो बार से टाला जा रहा है। वहीं बसपा सुप्रीमो कई बार 9 अक्तूबर को कांशीराम स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेती रही हैं।

सीजी: शिक्षिकाओं के हौसले को सलाम, बच्चों का भविष्य संवारने 9 माह की मासूम के साथ नदी पार कर पहुंचती हैं स्कूल

बलरामपुर , एजेंसी। कहते हैं कि अगर मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो रास्ते की बड़ी से बड़ी रुकावटें भी घुटने टेक देती हैं। ऐसा ही एक अद्भुत और प्रेरणादायक उदाहरण छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर ब्लॉक स्थित ढौरपुर पारा प्राथमिक स्कूल से सामने आया है। यहां पदस्थ दो महिला शिक्षिकाएं अपनी जान जोखिम में डालकर, उफनती नदी पार करके और पथरीले रास्तों पर 3 किलोमीटर पैदल चलकर रोज बच्चों को पढ़ाने पहुंचती हैं। इनमें से एक शिक्षिका तो अपनी महज 9 महीने की मासूम बच्ची को गोद में उठाकर नदी के तेज बहाव को पार करती हैं। शिक्षिका संध्या हलदर और कारमिला टोप्पो रोज अपनी स्कूटर मर्ना गांव में खड़ी करती हैं। इसके बाद शुरू होता है पहाड़ियों और पत्थरों से भरा 3 किलोमीटर का कठिन पैदल रास्ता। सफर का सबसे खौफनाक मोड़ तब आता है जब मोरान और इरिया नदी के संगम को पार करना पड़ता है। बारिश के दिनों में यहां पानी कमर से लेकर पेट तक आ जाता है। शिक्षिका संध्या हलदर बताती हैं जब पानी का बहाव तेज होता है, तो पैर काँपने लगते हैं लेकिन जब हम स्कूल पहुंचते हैं और बच्चे हमें देखकर खुश होते हैं तो सारी थकान और डर मिट जाता है। हम चाहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान न हो। शिक्षिकाओं के इस समर्पण की खबर सोशल मीडिया और मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए सामने आने के बाद बलरामपुर कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी ने उनके जज्बे की खुलकर तारीफ की है।

जबरन पाबंदी, शराब की लत का इलाज नहीं' : शराबबंदी पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को दी सख्त चेतावनी

नई दिल्ली, एजेंसी। शराब की त्रासदियों पर अंकुश लगाने के महाराष्ट्र के प्रयास पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चेतावनी दी कि जबरन संयम शराब की लत का इलाज नहीं है. शीर्ष अदालत ने 'महाराष्ट्र पॉइजन्स रूल्स' के उन प्रावधानों को रद्द कर दिया, जिसके तहत जहरीली शराब की त्रासदियों को रोकने के लिए गैर-दवा निर्माताओं को बेचने से पहले मेथनॉल में एक विशेष रंग और कड़वा पदार्थ मिलाना अनिवार्य किया गया था.

मेथनॉल में कड़वे और रंगीन पदार्थों को मिलाने की निरर्थकता पर जोर देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रसिद्ध लेखक मार्क टवेन का हवाला दिया, जिन्होंने कहा था, 'ऐसे सबूत सामने आए हैं जो साबित करते हैं कि शराबबंदी केवल नशे को दरवाजों के पीछे और अंधेरी जगहों पर धकेलती है, यह इसे ठीक नहीं करती या कम भी नहीं करती है.

जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने माना कि मुंबई में एक बड़ी जहरीली शराब त्रासदी के बाद 2011 की अधिसूचना के माध्यम से 'महाराष्ट्र पॉइज़न्स रूल्स' में शामिल किए गए नियम 18ए और 18बी, संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और 19(1)जी) (आजीविका/व्यापार का अधिकार) का उल्लंघन करते हैं. पीठ ने कहा कि मेथनॉल में कड़वा और रंगीन पदार्थ मिलाने से शराब की लत को दबाया नहीं जा सकता. इसकी अनुपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उत्पाद शुल्क कानूनों के तहत परिवहन और भंडारण के अधिक सख्त नियामक उपाय होने चाहिए. कोर्ट ने आगे कहा कि मौजूदा कदम पूरे उद्योग को ही खतरे में डाल देता है और यह 'पेड़ बचाने के चक्कर में पूरे जंगल को खो देने' जैसा होगा. पीठ ने फैसला सुनाया, 'हमारा यह सुविचारित मत है कि विवादित नियम आनुपार्किकता के परीक्षण में विफल रहते हैं, और गैर-दवा निर्माताओं के अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं. ' पीठ ने कहा कि शराब की लत से मजबूर लोगों को न तो स्वाद और न ही रंग रोक सकता है. साथ ही कोर्ट ने आगाह किया कि इस तरह के अत्यधिक नियामक नियंत्रण से वैध केमिकल व्यवसायों की बर्बादी का खतरा बढ़ जाता है. पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि इतिहास इस बात का गवाह है कि शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने से अक्सर शराब का कारोबार भूमिगत हो जाता है, जिससे अनियमित और जानलेवा शराब का चलन बढ़ जाता है. कोर्ट ने आगे कहा, 'गुजरात राज्य का ही मामला ले लीजिए. गुजरात राज्य में सख्त शराबबंदी नीति लागू है. यह एक ड्राई स्टेट है. इसके बावजूद, गुजरात के गठन और आजादी के बाद से वहां कम से कम दस बड़ी जहरीली शराब त्रासदियां हो चुकी हैं, जिनमें 600 से अधिक लोगों की जान गई है. ' पीठ ने कहा कि हाल ही में गुजरात के भावनगर और मध्य प्रदेश के सागर में हुई जहरीली शराब त्रासदियां, जिनमें क्रमशः लगभग 13 और 15 लोगों की जान गई थी, अधिकारियों को जागने और सख्त कदम उठाने की याद दिलाती हैं. शीर्ष अदालत ने जहरीली शराब की त्रासदियों को रोकने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कई उपायों का सुझाव दिया. कोर्ट ने नकली शराब के अवैध निर्माण, परिवहन और बिक्री को रोकने के लिए एक समन्वित और बहु-विभागीय दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया. महाराष्ट्र सरकार ने 1991 की जहरीली शराब त्रासदी के बाद इन नियमों को शामिल किया था, जिसमें मुंबई के अंधेरी स्थित 'छाया बार' से खरीदी गई नकली शराब पीने से लगभग 250 लोग प्रभावित हुए थे. पीठ ने कहा, 'शराब पीने वाले लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वे जिस चीज का सेवन कर रहे थे वह मेथनॉल था, जो किसी जहर से कम नहीं है. इसके परिणामस्वरूप, लगभग 93 लोगों की जान चली गई थी. '

पीठ ने उल्लेख किया कि मुंबई में 1991 की 'छाया बार' जहरीली शराब त्रासदी के बाद पार्थसारथी समिति का गठन किया गया था. पीठ ने कहा कि पार्थसारथी समिति की रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ने पर पता चलेगा कि शराब त्रासदियों के लिए केवल लाइसेंसधारियों द्वारा अवैध रूप से मेथनॉल बेचे जाने के अलावा भी कई अन्य कारण जिम्मेदार थे.

कोर्ट ने आगे कहा कि समिति द्वारा पहचाने गए अन्य कारणों में शामिल थे- अवैध और बिना लाइसेंस वाले चैनलों के माध्यम से मेथनॉल का डायवर्जन, एथिल अल्कोहल के मुकाबले एक सस्ते विकल्प के रूप में मेथनॉल की उपलब्धता, कानून प्रवर्तन एजेंसियों में भ्रष्टाचार, एथिल और मिथाइल अल्कोहल के बीच वास्तविक भ्रम, और चोरी. कोर्ट ने कहा कि विवादित नियमों द्वारा बनाए गए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बावजूद ये सभी कारण और वजहें लगातार काम करती रह सकती हैं।

नीतिश कुमार संग बीजेपी का रिश्ता सिर्फ सियासी तालमेल नहीं: रवि शंकर प्रसाद

नई दिल्ली, एजेंसी। बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने इस बात को खारिज कर दिया कि जेडी(यू) के साथ उनकी पार्टी का गठबंधन सिर्फ़ एक राजनीतिक तालमेल था। उन्होंने बिहार के विकास के लिए पार्टी प्रमुख नीतीश कुमार के 'असाधारण' काम की तारीफ़ की। एक निजी मीडिया के कार्यक्रम में बोलते हुए प्रसाद ने बताया कि नीतीश कुमार के साथ उनकी पार्टी के रिश्ते 2005 से 2007 के बीच शुरू हुए थे और इनकी नींव उस साझा लड़ाई में पड़ी थी जिसे उन्होंने 'जंगल राज' कहा था। प्रसाद ने इस बात पर ज़ोर दिया कि [illegible] ने वरिष्ठता का सम्मान किया और ज़्यादा सीटें होने के बावजूद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, और अब पार्टी अपना मुख्यमंत्री पाकर खुश है। साथ ही, उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि पूरा एनडीए - जद (यू), बीजेपी, एलजेपी,उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी शामिल हैं - मिलकर काम कर रहा है। भौगोलिकसंदर्भ

यह वीनर्स नकली दांतों से 300 गुना बेहतर है! और कीमत बहुत सस्ती है प्रसाद ने कहा कि भाजपा का एक लंबे समय से चला आ रहा राजनीतिक लक्ष्य अब पूरा हो गया है, क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्र में बिहार ही एकमात्र ऐसा राज्य था जहाँ पार्टी का अपना कोई मुख्यमंत्री नहीं था। बिहार के विकास का ज़िक्र करते हुए, प्रसाद ने पटना एयरपोर्ट के कायाकल्प, आठ वंदे भारत ट्रेनों, अटल पथ और जेपी गंगा पथ का उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि गंगा पर पाँच पुल बनाए जा रहे हैं और बाढ़ के दौरान सरकार की राहत कोशिशों को भी याद किया। अपने चुनाव क्षेत्र के बख्तियारपुर और फतुहा का ज़िक्र करते हुए, प्रसाद ने कहा कि उन्होंने लोगों की मदद के लिए खुद बाढ़ के पानी में उतरकर काम किया। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने हाल ही में तैनात दो [illegible] अधिकारियों को बाढ़-राहत कार्यों में शामिल किया, ताकि उन्हें ज़मीनी हालात की सीधी समझ मिल सके। प्रसाद ने उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की भी तारीफ़ की और कहा कि उन्होंने कई जगहों पर डिग्री कॉलेज खुलवाने और शिकायतों के समाधान के लिए एक पोर्टल शुरू करने में मदद की है। प्रसाद के अनुसार, इस पोर्टल को गोवा और गुजरात में भी अपनाया गया है; इसमें लंबित शिकायतों पर हर हफ्ते रिमाइंडर भेजे जाते हैं और अगर एक महीने के भीतर कोई जवाब नहीं मिलता, तो कार्रवाई की जाती है। उन्होंने [illegible] सेक्टर, स्किल सेंटर्स और एआई डेटा यूनिवर्सिटी के लिए योजनाओं का भी ज़िक्र किया, साथ ही कानून-व्यवस्था की स्थिति को सख्त बताया।

बरसाना में राधा अष्टमी पर उमड़ा आस्था का सैलाब, ब्रह्म मुहूर्त में हुआ राधा रानी का महा अभिषेक

मथुरा, एजेंसी। उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी मथुरा के बरसाना में शनिवार को राधा अष्टमी के पावन पर्व पर श्री राधा रानी मंदिर में श्रद्धालुओं का भारी सैलाब उमड़ पड़ा। देशभर से पहुंचे भक्तों ने राधा रानी के दर्शन कर पूजा-अर्चना की और जन्मोत्सव की खुशियों में शामिल हुए। इस दौरान, मंदिर परिसर और आसपास का क्षेत्र राधा रानी के जयकारों से गूंजता रहा। राधा अष्टमी के अवसर पर सुबह करीब 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में श्री राधा रानी का महा अभिषेक किया गया। धार्मिक परंपराओं के अनुसार अभिषेक में विभिन्न जड़ी-बूटियों, चांदी के कलश और अन्य पूजन सामग्री का प्रयोग किया गया। विधि-विधान और मंत्रोच्चार के बीच हुए इस विशेष अभिषेक के दौरान श्रद्धालुओं ने राधा रानी की भक्ति में लीन होकर दर्शन किए। राधा रानी के जन्मोत्सव को लेकर बरसाना में विशेष धार्मिक उत्साह देखने को मिला। मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं और पूरे बरसाना में भक्तिमय माहौल बना रहा। राधा अष्टमी को राधा रानी के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन व्रत रखने और विधि-विधान से राधा-कृष्ण की आराधना करने से जीवन में प्रेम, सुख और शांति आती है। यह त्योहार आमतौर पर मथुरा, वृंदावन और आसपास के ब्रज क्षेत्रों में मनाया जाता है। राधा को भगवान कृष्ण की 'ह्लादिनी शक्ति,' यानी आनंद देने वाली शक्ति, माना जाता है। उनके बिना, कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है। मान्यता है कि जो भक्त राधा अष्टमी के दिन पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा और व्रत करते हैं, उन्हें राधा रानी और भगवान कृष्ण दोनों का आशीर्वाद मिलता है। इससे जीवन में सुख-शांति आती है और पापों का नाश होता है।

हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, राधा रानी का जन्म बरसाना (उत्तर प्रदेश) में हुआ था। उनके पिता वृषभानु और माता कीर्तिदा थीं। एक प्रचलित कथा के अनुसार, राधा ने बचपन में अपनी आंखें तब तक नहीं खोलीं, जब तक कि उन्होंने पहली बार भगवान कृष्ण को नहीं देखा। जब कृष्ण उनके सामने आए, तब उन्होंने पहली बार अपनी आंखें खोलीं और उन्हें देखकर मुस्कुराईं।

मणिपुर में फिर से राष्ट्रपति शासन लगाने की उठी मांग, कुकी-जो फोरम ने कहा, 'नाकाम रही लोकप्रिय सरकार'

नई दिल्ली, एजेंसी। कुकी-जो फोरम ने मणिपुर में दोबारा राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग उठाई है. फोरम का कहना है कि 4 फरवरी, 2026 को बनी पॉपुलर सरकार किसी भी सरकार की पहली ड्यूटी जान की सुरक्षा को निभाने में नाकाम रही है. उन्होंने कहा कि संवैधानिक मशीनरी फिर से टूट गई है. राज्य में चल रहे संघर्ष पर शुक्रवार को एक दिन की कॉन्फ्रेंस में एकमत से एक प्रस्ताव पास हुआ. इस प्रस्ताव में राज्य में तुरंत फिर से राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई. इसमें आरोप लगाया गया कि इस साल फरवरी में बनी लोकप्रिय सरकार कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आम लोगों की जान बचाने में नाकाम रही है.

कुकी-जो विमेंस फोरम दिल्ली और एनसीआर द्वारा आयोजित की गई इस कॉन्फ्रेंस में अकेडेमिक्स, सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि और दूसरे हितधारकों एक साथ आए और राष्ट्रपति शासन हटने के बाद जारी हिंसा और विकास पर चर्चा की. ईटीवी भारत के पास मौजूद प्रस्ताव की कॉपी में कहा गया, 'मणिपुर में तुरंत फिर से राष्ट्रपति शासन लगाने का समय आ गया है.

फोरम ने आगे मांग की कि जब तक कुकी-जो गांवों को असरदार तरीके से सुरक्षित नहीं किया जा सकता, तब तक केंद्र सरकार राज्य के प्रशासन की सीधी जिम्मेदारी फिर से ले. कॉन्फ्रेंस में बोलने वालों ने चुनी हुई सरकार के फिर से आने के बाद बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता जताई. उन्होंने गृह मंत्रालय द्वारा नए एडवाइजर (नॉर्थईस्ट) की नियुक्ति के आसपास प्रशासनिक और राजनीतिक विकास के क्रम पर भी सवाल उठाए. जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रॉबर्ट थोंगखोलाल हाओकिप ने 4 फरवरी को राष्ट्रपति शासन हटने के बाद के विकास का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि एके मिश्रा ने परिवर्तनकाल के समय नई दिल्ली में कुकी-जो के प्रतिनिधि को बताया था कि वह एक उत्तराधिकारी के लिए रास्ता बना रहे हैं. प्रोफेसर हाओकिप ने बताया कि कुछ ही दिनों में गृह मंत्रालय ने 1974 बैच के रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी और इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर और जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी के चेयरमैन अजीत लाल को एडवाइजर (नॉर्थईस्ट) नियुक्त किया. लाल को नगा शांति वार्ता के साथ-साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस फ्रेमवर्क के तहत कुकी-जो समूह के साथ बातचीत की जिम्मेदारी दी गई थी. यह कहते हुए कि वह लाल के सर्विस रिकॉर्ड पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, हाओकिप ने कहा कि आज की बैठक में केंद्र सरकार से कुकी-जो के आम लोगों पर नए हमलों के साथ हुई घटनाओं के बारे में सफाई मांगी गई. उन्होंने कहा, 'हम किसी भी अधिकारी के सर्विस रिकॉर्ड पर केस नहीं करते हैं।

तमिलनाडु में नवजातों के लिए सोने की अंगूठी योजना 28 सितंबर से : सीएम विजय करेंगे शुभारंभ

चेन्नई, एजेंसी। तमिलनाडु सरकार ने नवजात शिशुओं के कल्याण और सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए अपनी महत्वाकांक्षी योजना 'थाईमामन थंगा मोथिरा थिट्टम' (मामा की सोने की अंगूठी योजना) के शुभारंभ की तारीख घोषित कर दी है। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय 28 सितंबर 2026 को इस योजना की औपचारिक शुरुआत करेंगे। इसके तहत प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले प्रत्येक नवजात शिशु को उपहार स्वरूप 1 ग्राम सोने की अंगूठी प्रदान की जाएगी। सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के बाद इस तारीख पर अंतिम मुहर लगाई गई। यह योजना सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कझगम के प्रमुख चुनावी वादों में शामिल रही है, जिसे लागू करने के लिए 23 जून 2026 को सरकारी शासनादेश जारी किया गया था। पहले चरण में 1.28 लाख अंगूठियां तैयार, सीरियल नंबर से होगी ट्रैकिंग

पारदर्शी वितरण: समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, पहले चरण के तहत वितरण के लिए 1.28 लाख सोने की अंगूठियां खरीदी जा चुकी हैं। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी रोकने के लिए प्रत्येक अंगूठी पर विशिष्ट सीरियल नंबर अंकित किया गया है। डिस्चार्ज के समय उपहार: नवजात और प्रसूता को अस्पताल से छुट्टी (डिस्चार्ज) मिलने के समय ही यह अंगूठी सौंपी जाएगी।

पूर्व प्रभाव से लाभ: योजना का लाभ 22 जून (मुख्यमंत्री के जन्मदिन) से 28 सितंबर के बीच सरकारी अस्पतालों में जन्म ले चुके बच्चों को भी दिया जाएगा। इसके लिए राज्यभर में 107 विशेष वितरण केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां प्रतिदिन 100 बच्चों को अंगूठी वितरित करने की व्यवस्था की गई है।

पात्रता और आवश्यक शर्तें : योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सरकार ने स्पष्ट मानक तय किए हैं: नवजात की माता का तमिलनाडु का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। प्रसव पूर्व मां का गर्भावस्था और बाल ट्रैकिंग प्रणाली तथा प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य पोर्टल पर पंजीकृत होना आवश्यक है, जिसके आधार पर पहचान पत्र जारी होता है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, तमिलनाडु में प्रतिवर्ष लगभग 7.80 लाख बच्चों का जन्म होता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6 (हस्र॥स-6) के अनुसार, राज्य में 99.9 प्रतिशत प्रसव अस्पतालों (संस्थागत) में होते हैं। इनमें से लगभग 4.20 लाख प्रसव (कुल का लगभग 53 प्रतिशत) सरकारी अस्पतालों में संपन्न होते हैं।

महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित किसानों को 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर दे सरकार: शरद पवार

मुंबई, एजेंसी। राकांपा (शरदचंद्र पवार) प्रमुख शरद पवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर कम बारिश वाले तालुकों में सूखा घोषित करने की मांग की है। उन्होंने प्रभावित किसानों को 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर और खेतिहर मजदूरों को 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का आग्रह किया। पवार के अनुसार राज्य के 31 जिलों में कम वर्षा के कारण फसलें बर्बाद हो चुकी हैं।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के अध्यक्ष शरद पवार ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से अपील की कि वह कम बारिश का सामना करने वाले तालुकों में सूखा घोषित करें और प्रभावित किसानों को कम से कम 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से आर्थिक सहायता दें। पवार ने बुधवार को मुख्यमंत्री को लिखे एक पत्र में दावा किया कि राज्य के 36 में से 31 जिलों में कम बारिश के कारण सोयाबीन, कपास और दाल जैसी खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं, साथ ही बुआई का रकबा भी काफी कम हो गया है और पेयजल व चारे की भारी किल्लत पैदा हो गई है। उन्होंने सरकार से मांग की कि वह औपचारिकताओं की प्रतीक्षा किये बिना सूखा घोषित करे और प्रभावित इलाकों को तुरंत राहत पहुंचाए। पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों को प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपये और खेतिहर मज़दूर परिवारों को 25,000 रुपये प्रति परिवार की दर से विशेष सहायता देने की भी मांग की। उन्होंने कृषि ऋण माफी योजना को तुरंत लागू करने और नयी फसल के लिए ऋण उपलब्ध कराने की भी मांग की। पवार ने पत्र में उन किसानों के लिए प्रोत्साहन राशि 50,000 रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये करने की मांग की जो नियमित रूप से कर्ज चुकाते हैं।

उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने 2025-26 में फसल ऋण लिया था लेकिन इस साल भुगतान नहीं कर पाए, उन्हें भी कर्ज माफी योजना में शामिल किया जाए। पवार ने एक रुपये वाली फसल बीमा योजना को पिछली तारीख से लागू करने और पिछले साल बेमौसम बारिश से हुए फसल के नुकसान के लिए घोषित ?17,000 प्रति हेक्टेयर की सहायता राशि तुरंत जारी करने की भी मांग की। राकांपा(शप) अध्यक्ष ने सूखे जैसे हालात का सामना कर रहे इलाकों के लिए रोजगार गारंटी योजना के तहत खेती और जल संरक्षण से जुड़ी विशेष योजनाएं संचालित करने और बागों को बचाने के लिए पानी के टैंकर की व्यवस्था करने की मांग की।

पवार ने कहा कि राज्य के 36 में से 31 जिलों में औसत से काफी कम बारिश हुई है। उन्होंने कहा कि एक जून से 15 सितंबर के बीच राज्य में 648 मिमी बारिश हुई, जो औसत से 19 प्रतिशत कम है। उन्होंने कहा कि मुंबई, रायगढ़, पालघर और विदर्भ सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में शामिल हैं।

आईआईटी बॉम्बे: छात्र की मौत के बाद हंगामा; परीक्षा में चैटजीपीटी के इस्तेमाल पर विवाद से बढ़ी बात?

मुंबई, एजेंसी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) बॉम्बे में बीटेक के दूसरे वर्ष के एक छात्र ने शुक्रवार को कथित तौर पर आत्महत्या की।बताया जा रहा है कि परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन इस्तेमाल करते पकड़े जाने के बाद उसने यह कदम उठाया। वहीं, छात्रों ने आज आईआईटी प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। छात्रों ने प्रशासन से मामले में जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग की। उनका कहना है कि इस साल ऐसी चार घटनाएं हो चुकी हैं। इनमें दो घटनाएं पिछले दो महीनों में हुई हैं। छात्र की पहचान साहिल वकोडे के रूप में हुई है। अधिकारियों के मुताबिक, वह ऊर्जा विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग का छात्र था। छात्र ने परीक्षा के दौरान सवालों के जवाब पाने के लिए परीक्षा का प्रश्नपत्र चैटजीपीटी पर अपलोड किया था। अधिकारियों ने बताया कि छात्र के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी। इस मामले पर प्रशिक्षक और विभागाध्यक्ष ने भी छात्र से बात की थी। उन्होंने उसे समझाया था। साथ ही भरोसा दिलाया था कि इस घटना का उसके पढ़ाई और शैक्षणिक करियर पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। बातचीत के बाद छात्र अपने छात्रावास के कमरे में वापस चला गया। बाद में शाम को वह अपने कमरे में मृत पाया गया। आईआईटी बॉम्बे ने एक बयान जारी किया। संस्थान ने कहा कि वह एक छात्र की मौत से 'बहुत दुखी' है। बयान में कहा गया, संस्थान छात्र के दोस्तों, सहपाठियों, शिक्षकों और इस दुखद घटना से प्रभावित अन्य लोगों को सहायता दे रहा है। मौत से जुड़ी परिस्थितियों की उचित अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है'।

प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने क्या कहा : वकोडे की मौत की जानकारी सामने आने के बाद आईआईटी पवई परिसर में छात्रों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने आरोप लगाया कि संस्थान घटना से जुड़ी पूरी सच्चाई सामने नहीं बता रहा है। छात्रों का दावा है कि परीक्षा में नकल करने के आरोपी छात्र को कथित तौर पर एक साल के निलंबन की धमकी दी गई थी। छात्रों ने कहा कि अगर उसे निलंबित किया जाता, तो उसे छात्रावास खाली करना पड़ता। उसे परिसर से बाहर रहना पड़ता। छात्रों के अनुसार, ऐसी कार्रवाई से छात्र का इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम भी प्रभावित हो सकता था। चार साल का पाठ्यक्रम बढ़कर पांच साल या उससे भी ज्यादा हो सकता था। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने आरोप लगाया कि अनुशासनात्मक कार्रवाई को लेकर डर और दबाव ने वाकोडे को यह कदम उठाने के लिए प्रभावित किया हो सकता है। हालांकि, इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कहा कि वे यह जानना चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। इसके पीछे की वजह क्या है, इसकी जानकारी छात्रों को नहीं दी जा रही है। छात्रों ने डीन, निदेशक और प्रशासन से इस मामले पर रिपोर्ट देने की मांग की है। छात्रों का कहना है कि रिपोर्ट में यह साफ होना चाहिए कि मामले की जांच कैसे होगी। इसमें जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की बात भी होनी चाहिए। साथ ही छात्रों ने मांग की है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। छात्र अंश ने कहा कि छात्र इस घटना से बहुत दुखी हैं।

ईशा मालवीय की बॉलीवुड में एंट्री

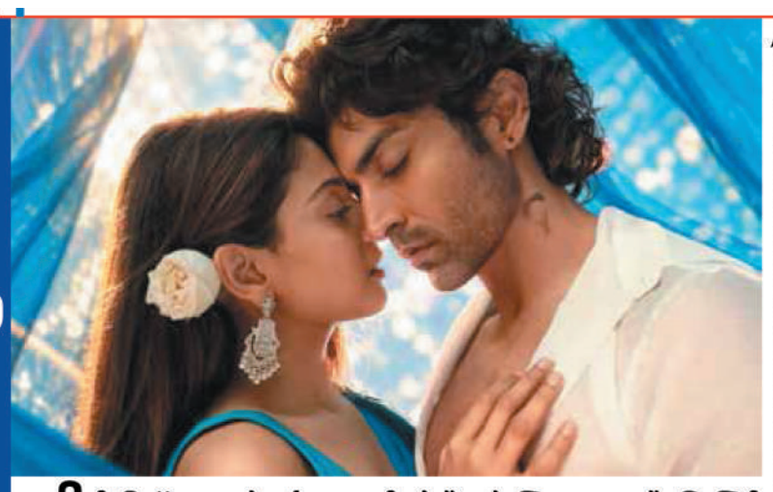

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस ईशा मालवीय के फैंस के लिए गुड न्यूज है। रिएलिटी शो, टीवी सीरियल और म्यूजिक वीडियो के बाद ईशा बॉलीवुड में एंट्री करने वाली हैं। जी हां, जल्द ही एक्ट्रेस की पहली फिल्म रिलीज हो रही है।

ईशा मालवीय फिल्म 'तुम मेरे हो' से अपना बॉलीवुड डेब्यू कर रही हैं। इस फिल्म में उनके साथ गुरमीत चौधरी लीड रोल में हैं। फिल्म का फर्स्ट लुक भी सामने आ गया है, जिसमें ईशा और गुरमीत की कैमेस्ट्री साफ झलक रही है। एक पोस्टर पर लिखा है, 'कभी-कभी प्यार में पड़ना आसान होता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, वही असली कहानी है।'इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म सिर्फ प्यार की शुरुआत नहीं, बल्कि उसके बाद आने वाले रिश्ते और भावनाओं की कहानी भी दिखाएगी। पोस्टर्स के साथ ही फिल्म की रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया है। चलिए जान लेते हैं कि ईशा मालवीया और गुरमीत चौधरी की ये फिल्म कब रिलीज होने वाली है।तुम मेरे हो के साथ ईशा मालवीय टीवी और म्यूजिक वीडियोज के बाद अब बड़े पर्दे पर कदम रखने जा रही हैं। फिल्म से पोस्टर्स सामने आए हैं उसमें ईशा और गुरमीत की लव कैमेस्ट्री साफ दिखाई दे रही है। एक पोस्टर नें दोनों किस करते नजर आ रहे हैं। वहीं, बाकी पोस्टर में दोनों स्टार्स एक दूसरे में खोए हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी पोस्टर से ही आप समझ सकते हैं कि फिल्म में दोनों की कैमेस्ट्री कितनी ज्यादा अच्छी होने वाली है।पोस्टर्स देख फैंस भी काफी एक्साइटेड हो गए हैं और फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। वहीं, कमेंट्स में फैंस ईशा को फिल्म के लिए बधाई भी दे रहे हैं। रिलीज डेट की बात करें तो, ये फिल्म 23 अक्तूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

दूसरे बेबी के जन्म से पहले दीपिका ने लिया बप्पा का आशीर्वाद

बॉलीवुड के चर्चित कपल रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण शुक्रवार को मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे। दोनों ने यहां भगवान गणेश के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। इस दौरान रणवीर के माता-पिता भी उनके साथ नजर आए। मंदिर पहुंचते ही कपल ने पूरे परिवार के साथ पूजा-अर्चना की। दीपिका इन दिनों अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी को लेकर चर्चा में हैं और मंदिर में भी उनका बेबी बंप साफ नजर आया। मंदिर दर्शन के दौरान दीपिका पादुकोण ने ऑरेंज और पर्पल रंग का कुर्ता सेट पहना हुआ था। वहीं रणवीर सिंह पर्पल कुर्ते के साथ सफेद पैंट में नजर आए। दोनों का यह सिंपल और ट्रेडिशनल लुक सोशल मीडिया पर भी चर्चा में है। परिवार के साथ मंदिर पहुंचने के दौरान दोनों ने भगवान गणेश के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की।

सिद्धिविनायक मंदिर जाने से ठीक एक दिन पहले रणवीर सिंह मुंबई के मशहूर लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे थे। गणपति उत्सव के मौके पर रणवीर ने बप्पा के सामने माथा टेका और हाथ जोड़कर प्रार्थना की। इस दौरान अभिनेता गुलाबी रंग के कुर्ते में दिखाई दिए थे। गणपति उत्सव के बीच लगातार मंदिरों में दर्शन के लिए पहुंच रहे रणवीर का धार्मिक अंदाज फैंस को भी पसंद आ रहा है। रणवीर और दीपिका का सिद्धिविनायक मंदिर से खास कनेक्शन भी रहा है। इससे पहले दोनों 6 सितंबर 2024 को यहां पहुंचे थे। खास बात यह है कि उस दर्शन के महज दो दिन बाद यानी 8 सितंबर को उनके घर बेटी का जन्म हुआ था। उन्होंने अपनी बेटी का नाम दुआ रखा। ऐसे में इस बार भी दूसरी प्रेग्नेंसी के दौरान सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचना उनके लिए भावनात्मक रूप से खास माना जा रहा है।

'इंडिया के टॉप 1%' शो लेकर आ रहे अनिल कपूर

अनिल कपूर स्टार प्लस के 'इंडिया के टॉप 1%- द अनिल कपूर शो' के ग्रैंड प्रीमियर के साथ टेलीविजन पर धमाकेदार आगाज करने के लिए तैयार हैं। इस गेम शो में 100 प्रतियोगी अपनी सूझबूझ, बारीक नजर और रोजमर्रा की समझ के दम पर टॉप 1% में जगह बनाने और 1 करोड़ रुपए तक जीतने के लिए खेलेंगे। हालाँकि, इस खेल का रोमांच केवल मंच पर मौजूद प्रतियोगियों तक सीमित नहीं रहेगा।

जियोहॉटस्टार के 'प्ले अलॉन्ग' फीचर के जरिए दर्शक भी घर बैठे रियल टाइम में सवालों के जवाब दे सकेंगे और खेल का हिस्सा बन पाएंगे। इतना ही नहीं, उनके पास स्मार्टफोन और स्मार्ट टीवी जैसे शानदार इनाम जीतने का मौका भी होगा। शो के दौरान अपने तिलक नगर के दिनों को याद करते हुए अनिल कपूर ने एक मजेदार किस्सा साझा किया। उन्होंने बताया, "हम चेंबूर के तिलक नगर में रहते थे, जहाँ छोटी-बड़ी कई शादियाँ होती रहती थीं। मैं और मेरे दोस्त मिलकर उन शादियों में पहुँच जाते थे। मुफ्त की चीज किसे पसंद नहीं होती? चाहे कोई तोहफा हो या खाना, अगर कुछ मुफ्त मिल रहा हो तो लोग कहीं भी पहुँच जाते हैं।"उन्होंने आगे कहा, मैं तो वहाँ सिर्फ गोल्ड स्पॉट और मैंगोला पीने जाता था। हम 'हैलो, हैलो, कैसे हैं आप?' कहते हुए अंदर घुसते और सीधे काउंटर पर पहुँच जाते थे। वहाँ हम गोल्ड स्पॉट और मैंगोला की 11 से 12 बोतलें पी जाते थे। आपने वह कहावत तो सुनी ही होगी, 'बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना।' लेकिन, असल में इसे होना चाहिए, बेगानी शादी में अनिल कपूर दीवाना!"

अक्षय कुमार की 'समुक' में हुई रजत कपूर की एंट्री

बॉलीवुड के 'खिलाड़ी' कुमार' यानी अक्षय कुमार एक बार फिर सिनेमाघरों में दर्शकों के लिए कुछ बिल्कुल नया और अनोखा लेकर आने की तैयारी कर रहे हैं। अपनी फिल्मों के चुनाव में विविधता लाने के लिए मशहूर अक्षय अब भारतीय सिनेमा में एक नए जॉनर को एक्सप्लोर कर रहे हैं। एलियन और साइंस-फिक्शन की पृष्ठभूमि पर बन रही उनकी बहुचर्चित एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'समुक' को लेकर फिल्म गलियारों में जबरदस्त चर्चा है। अब इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट सामने आया है—दिग्गज अभिनेता और फिल्ममेकर रजत कपूर भी इस बहुप्रतीक्षित फिल्म की स्टारकास्ट का हिस्सा बन चुके हैं। इंडस्ट्री के सबसे बहुमुखी अभिनेताओं में से एक रजत कपूर अपनी दमदार और बारीक परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं।

मानसून वेडिंग, भेजा फ्राई, कपूर एंड संस, दृश्यम सीरीज और हाल ही में आई ओटीटी रिलीज 'रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स' जैसी फिल्मों के जरिए उन्होंने साबित किया है कि वे हर किरदार में जान फूंक देते हैं। खबरों के अनुसार कनिष्क वर्मा के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में रजत कपूर एक बेहद महत्वपूर्ण और प्रभावकारी भूमिका निभाएंगे। उनके शामिल होने से फिल्म की स्टारकास्ट को एक अलग ही गंभीरता और गहराई मिली है।

यूके में चल रही है इंटरनेशनल लेवल की शूटिंग

विपुल अमृतलाल शाह के बैनर 'सनशाइन पिक्चर्स' के तले बन रही और आशिन ए शाह द्वारा को-प्रोड्यूस की जा रही फिल्म 'समुक' की शूटिंग इस समय यूके की खूबसूरत और सस्पेंस भरे लोकेशंस पर चल रही है। मेकर्स इस फिल्म को सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि ग्लोबल ऑडियंस को ध्यान में रखकर इंटरनेशनल लेवल पर तैयार कर रहे हैं।

नहीं हुजूर, मैं काम से रिटायर नहीं हो रहा हूं: अमिताभ बच्चन

सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने काम से रिटायरमेंट लेने की उड़ रही अफवाहों पर खुद विराम लगा दिया है। बिग बी ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल उनका सेवानिवृत्त होने का कोई इरादा नहीं है। दरअसल, दिग्गज अभिनेता के हालिया ब्लॉग पोस्ट के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि वे अपने व्यस्त करियर से दूरी बनाने पर विचार कर रहे हैं। इन अफवाहों को खारिज करते हुए, मेगास्टार ने फिर से एक ब्लॉग पोस्ट किया और अपनी पहले की बात को स्पष्ट किया। उन्होंने अपने प्रशंसकों और मीडिया को संबोधित करते हुए लिखा, नहीं हुजूर, मैं काम से रिटायर नहीं हो रहा हूं, अंग्रेजी में इसका मतलब है कि मैं अब सोने जा रहा हूं और आपको वहां आने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है। इस स्पष्टीकरण से उन्होंने उन सभी अटकलों पर पूर्णविराम लगा दिया, जो उनके पहले के पोस्ट से पैदा हुई थीं। यह सारा भ्रम तब पैदा हुआ जब दिग्गज अभिनेता ने अपने पिछले ब्लॉग में लिखा था कि कैसे उनकी कुछ ब्लॉग एंट्री को अक्सर गलत समझा जाता है और जिस तरह से उनके शब्दों का अर्थ निकाला जाता है और रिपोर्ट किया जाता है, उस पर मजाक उड़ाया जाता है। उन्होंने अपने उस खास पोस्ट को और मैं रिटायर हो गया शब्दों के साथ खत्म किया था, जिससे बाद में यह अंदाजा लगने लगा कि क्या वह अपने अभिनय करियर या पेशेवर प्रतिबद्धताओं से सेवानिवृत्त होने की बात कर रहे थे। इस एक वाक्य को कई लोगों ने उनके करियर के समापन के संकेत के रूप में व्याख्या कर लिया था। अपनी नवीनतम पोस्ट में, अमिताभ बच्चन ने साफ किया कि रिटायर शब्द का इस्तेमाल उनके द्वारा सोने जाने के संदर्भ में किया गया था, न कि अभिनय या अपने पेशेवर दायित्वों से दूर जाने के लिए। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनके प्रशंसक और मीडिया उनके शब्दों का सही अर्थ समझें और किसी भी गलतफहमी से बचें। बता दें कि अमिताभ बच्चन अभी कौन बनेगा करोड़पति का 18वां सीजन होस्ट कर रहे हैं। इस लोकप्रिय क्विज शो से वह दो दशक से भी ज्यादा समय से जुड़े हुए हैं। यह शो पहली बार वर्ष 2000 में शुरू हुआ था,जिसमें अमिताभ बच्चन ने होस्ट का रोल निभाया था और इस क्विज शो को भारतीय टेलीविजन की सबसे प्रतिष्ठित फ्रेंचाइजी में से एक बना दिया था। उनकी अद्भुत मेजबानी, गर्मजोशी और ज्ञान ने इस शो को घर-घर में लोकप्रिय बनाया है।

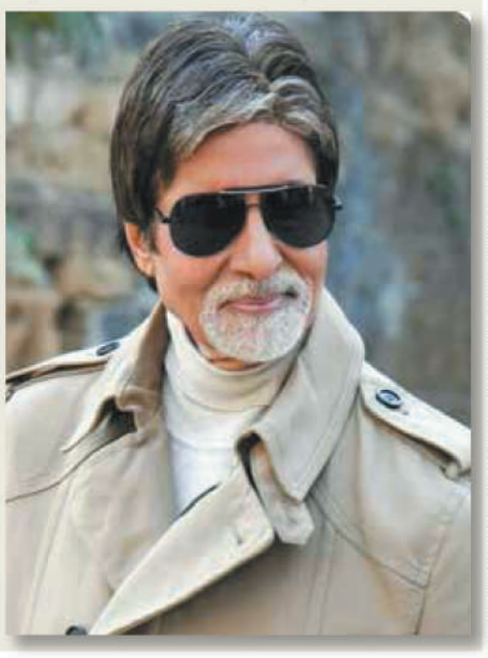

ऑस्कर 2027 में भारत की ओर से जाएगी 'गोंधल'

ऑस्कर 2027 में भारत की तरफ से कौन-सी फिल्म दावेदारी पेश करेगी, इसका फैसला हो चुका है। मराठी सिनेमा के लिए एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है। कोई बॉलीवुड नहीं बल्कि फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने मराठी फिल्म 'गोंधल' को ऑस्कर 2027 के लिए भारत की आधिकारिक एंट्री के तौर पर चुना है। फिल्म का चयन होने के बाद अब यह अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। अपनी कहानी और विषय को लेकर चर्चा में रही इस फिल्म से अब देशभर के सिनेमा प्रेमियों की उम्मीदें जुड़ गई हैं। ऑस्कर की रेस में भारत की ओर से 'गोंधल' का पहुंचना क्षेत्रीय सिनेमा की बढ़ती ताकत और उसकी कहानियों की व्यापक स्वीकार्यता को भी दर्शाता है। अब यह फिल्म बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। खास बात यह है कि इस साल देश की अलग-अलग भाषाओं में बनी 33 फिल्मों ने ऑस्कर के लिए अपनी दावेदारी पेश की थी। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच चयन समिति ने 'गोंधल' को आगे भेजने का फैसला किया। अब 'गोंधल' के सामने अगली चुनौती अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी जगह बनाने की है। भारत की ओर से चुने जाने के बाद फिल्म की यात्रा अब ऑस्कर की आगे की चयन प्रक्रिया तक पहुंचेगी।

मराठी फिल्म 'गोंधल' की कहानी ग्रामीण महाराष्ट्र की पृष्ठभूमि में होने वाले पारंपरिक गोंधल अनुष्ठान के बीच आकार लेती है। फिल्म की मुख्य किरदार सुमन एक ऐसे विवाह में फंस जाती है, जिसमें उसे आर्थिक रूप से संपन्न आनंद से शादी करनी पड़ती है, जबकि उसका दिल गोंधली कलाकार साहेबा के लिए धड़कता है। इस रिश्ते से बाहर निकलने के लिए सुमन एक खतरनाक योजना बनाती है। वह आनंद के चचेरे भाई सरजेराव की उसके प्रति दीवानगी का फायदा उठाती है और उसे ऐसे अपराध की ओर धकेलती है, जिसे वह खुद अंजाम नहीं दे सकती। फिल्म में गोंधल की रातभर चलने वाली परंपरा, संगीत और धार्मिक अनुष्ठान कहानी को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं। प्रेम, लालच, सत्ता, छल और आजादी की चाह के बीच कहानी धीरे-धीरे एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर का रूप लेती है। मराठी फिल्म 'गोंधल' का निर्देशन संतोष डावखर ने किया है। उन्होंने ही फिल्म की कहानी और पटकथा भी लिखी है। फिल्म में किशोर कदम, इशिता देशमुख, योगेश सोहोनी और निषाद भोईर प्रमुख भूमिकाओं में हैं।

छोटा होगा 'रामायण' का इंग्लिश वर्जन

रणबीर कपूर की 'रामायण' का पहला पार्ट दिवाली पर रिलीज किया जाएगा। कुछ वक्त पहले ही फिल्म का ट्रेलर आया था, जिसे लोगों का मिलाजुला रिस्पॉन्स मिला है। हर बार की तरह लोगों का कहना है कि भारतीय टच की फिल्म में कमी है। तो किसी ने लिखा कि VFX बहुत ओवर हैं और कुछ राक्षस हॉलीवुड वाली वाइब दे रहे हैं। पर इन सबके बीच मेकर्स को पूरा विश्वास है कि फिल्म अच्छा कारोबार करेगी और लगातार काम निपटा रहे हैं। खैर, इस फिल्म को बड़े लेवल पर ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचाया जा रहा है। अब खबर आई कि मेकर्स इंडियन और इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए अलग-अलग वर्जन तैयार कर रहे हैं।

वहीं हिंदी वर्जन से इंग्लिश कट 30 मिनट छोटा होगा। हाल ही में एक रिपोर्ट छपी। जिससे पता लगा कि 'रामायण' के इंग्लिश वर्जन में कोई गाना नहीं होगा। साथ ही और कुछ सीन भी छोटे किए जाएंगे ताकि ये इंटरनेशनल दर्शकों को पसंद आए। जहां इंडियन ऑडियंस तीन घंटे से ज्यादा लंबी और गानों वाली फिल्में देख लेते हैं, वहीं ग्लोबल दर्शकों के मामले में ऐसा नहीं है, इसलिए प्रोड्यूसर्स ने यह फैसला लिया। दरअसल रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश की फिल्म 'रामायणः पार्ट 1' का इंटरनेशनल वर्जन तैयार किया जा रहा है। जो क्लियर हो चुका है कि 30 मिनट छोटा होगा। जबकि, भारत और भारतीय डायस्पोरा के लिए रिलीज होने वाले हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम वर्जन्स अपनी पूरी लंबाई, गानों के साथ सिनेमाघरों में उतरेंगे। क्योंकि मेकर्स इसे इंटरनेशनल-लेवल के अडैप्टेशन के तौर पर पेश कर रहे हैं। वहीं, गाने कहानी को आगे नहीं बढ़ाते, बल्कि भारतीय दर्शकों के लिए कहानी को और बेहतर बनाते हैं। माना जा रहा है कि यह फिल्म इस साल की सबसे बड़ी थिएटर रिलीज में से एक होगी।

गणेश चतुर्थी पर्व मनाना मेरी सास ने शुरु किया था: सुनीता आहूजा

हाल ही में गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर अभिनेता गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने अपने घर में गणपति महाराज का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर सुनीता आहूजा ने बताया कि उनके घर में गणपति स्थापना की यह प्रथा गोविंदा की मां ने शुरू की थी, और वे इस परंपरा को पूरे भक्तिभाव से आगे बढ़ा रही हैं। गणेश चतुर्थी मनाने के पीछे की वजह बताते हुए सुनीता आहूजा ने कहा, गणेश चतुर्थी पर्व मनाना मेरी सास ने हमारे पुराने ऑफिस से शुरू किया था। तब से यह प्रथा चली आ रही है, तो मैंने सोचा कि जब तक जीवित हूं, तब तक तो गजानन को घर पर लेकर आऊंगी। अब ये प्रथा चलती रहेगी क्योंकि गणेश भगवान हमारे प्रथम देवता हैं, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए अपने परिवार की इस परंपरा और आगामी परियोजनाओं के बारे में कई खुलासे किए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गणेश भगवान उनके परिवार के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और वे इस परंपरा को पूरी श्रद्धा के साथ निभाती हैं। पिछले एक साल में बप्पा की कृपा का जिक्र करते हुए सुनीता आहूजा ने अपनी हालिया सफलताओं को साझा किया। उन्होंने कहा, आखिरी साल मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था और इस बार मैंने दो शोज किए हैं, जिनमें मां है ना और लॉकअप-2 शामिल है। सबसे खुशी की बात यह है कि मैंने अपने बेटे यशवर्धन आहूजा के साथ एक फिल्म की है, जिसके निर्देशक साजिद खान और प्रोड्यूसर एकता कपूर हैं। तो बप्पा ने मुझे इतना नाम, इज्जत और शोहरत दी है। यह पर्व मेरे लिए बहुत खास है, बप्पा को मैं नाचते गाते हुए ही घर में लेकर आई हूं। यह खुलासा उनके प्रशंसकों के लिए एक सुखद आश्चर्य है, क्योंकि वे अपने बेटे के साथ पहली बार बड़े पर्दे पर नजर आएंगी। उन्होंने बताया कि वे गणपति को डेढ़ दिन के लिए अपने घर में रखती हैं।

अजय देवगन की 'दृश्यम 3' तोड़ पाएगी मोहनलाल का रिकॉर्ड?

इस साल जिन बड़ी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार हो रहा है, उसमें अजय देवगन की 'दृश्यम 3' भी शामिल है. यूं तो मोहनलाल की मलयालम फिल्म पहले ही रिलीज हो चुकी है. जो पहले अजय देवगन के लिए खतरा बताई जा रही थी. पर जैसा इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्म किया है, उसके बाद से ही फैन्स की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं. जी हां, अजय देवगन की 'दृश्यम 3' 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. फिल्म का धांसू ट्रेलर आ चुका है. पर बड़ा सवाल है कि क्या मोहनलाल की फिल्म का रिकॉर्ड अजय देवगन तोड़ पाएंगे. इसके लिए 200 करोड़ रुपये से ज्यादा एक्टर को कमाने होंगे.मोहनलाल की 'दृश्यम 3' सिनेमाघरों में 21 मई 2026 को रिलीज हुई थी. इस बार डायरेक्टर जीतू जोसेफ ने केवल सस्पेंस और ट्विस्ट पर ध्यान नहीं दिया था. बल्कि जॉर्जकुट्टी के डर, उसके गिल्ट तनाव पर ज्यादा फोकस किया है.

जिसके इमोशनल एक्सप्रेशंस को काफी तारीफ भी मिली थी। पर फिल्म से जैसी उम्मीदें थी, उतना भारतीय बॉक्स ऑफिस पर नहीं कमा पाई। फिल्म ने दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस से 239.83 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। अब फैन्स के लिए खास बात है कि अजय देवगन की फिल्म की कहानी अलग है।अजय देवगन की 'दृश्यम 3' की कहानी इस बार मोहनलाल की फिल्म से अलग है। जो फैसला काफी पहले ही ले लिया गया था। मेकर्स पहले ही जानते थे कि मोहनलाल की फिल्म को जल्दी रिलीज कर दिया जाएगा। अजय के हिंदी वर्जन में इस बार विजय सलगांवकर के सामने काफी नई मुश्किलें देखने को मिलेगी।

ब्राह्मण जन्म से नहीं, विचार, त्याग और चरित्र से होता है: विधायक अनुज शर्मा

रायपुर के वृंदावन हॉल में आयोजित 'कुटुंब प्रबोधन एवं शिक्षक सम्मान समारोह' में उत्कृष्ट शिक्षकों को किया गया सम्मानित; भगवान परशुराम को बताया शास्त्र और शस्त्र का अद्भुत संतुलन।

रायपुर । छत्तीसगढ़ प्रांतीय अखंड ब्राह्मण समाज द्वारा सिविल लाइन्स स्थित वृंदावन हॉल में 'कुटुंब प्रबोधन एवं शिक्षक सम्मान समारोह' का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए क्षेत्रीय विधायक अनुज शर्मा ने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिक्षक-शिक्षिकाओं को शॉल, श्रीफल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। समारोह का शुभारंभ भगवान परशुराम के तैलचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ।

सनातन की ज्ञान-परंपरा है विप्र समाज

समारोह को संबोधित करते हुए विधायक अनुज शर्मा ने कहा कि समाज के सर्वांगीण विकास में कुटुंब और शिक्षा की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ब्राह्मण का अर्थ केवल जाति या जन्म से नहीं, बल्कि विचार, ज्ञान, त्याग और चरित्र से है। इतिहास गवाह है कि जब-जब समाज में अज्ञानता का अंधकार छाया, तब-तब विप्र समाज ने ज्ञान का दीप जलाकर राष्ट्र निर्माण में अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभाई है।

शास्त्र और शस्त्र के संतुलन पर जोर

भगवान परशुराम के आदर्शों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि उनका जीवन हमें 'शास्त्र और शस्त्र' के अद्भुत संतुलन का संदेश देता है। वे ज्ञान के सागर भी थे और अन्याय के खिलाफ न्याय के प्रतीक भी। विधायक ने कहा कि आज बच्चों को आधुनिक से आधुनिक शिक्षा देने के साथ-साथ अपनी जड़ों, धर्म और संस्कृति से मजबूती से जोड़े रखना आवश्यक है।

कुटुंब प्रबोधन और शिक्षकों का योगदान

बदलते दौर में पारिवारिक मूल्यों पर जोर देते हुए विधायक शर्मा ने कहा कि आधुनिक युग में जहां संयुक्त परिवार और सांस्कृतिक मूल्य कमजोर हो रहे हैं, वहां कुटुंब प्रबोधन का यह प्रयास सराहनीय है। उन्होंने शिक्षकों को राष्ट्र का वास्तविक शिल्पकार बताते हुए कहा कि शिक्षक केवल पुस्तकें नहीं पढ़ाते, बल्कि आने वाली पीढ़ी के चरित्र का निर्माण करते हैं।

गरिमामयी उपस्थिति

कार्यक्रम के अंत में सभी ने सुसंस्कृत समाज और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण का संकल्प लिया। इस अवसर पर प्रकाश धर दीवान, भारती शर्मा सहित छत्तीसगढ़ प्रांतीय अखंड ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी, प्रबुद्ध नागरिक और बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे।

लघु उद्योगों और एमएसएमई को मजबूत बनाकर विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का रोडमैप तैयार कर रही सरकार : वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी

रायपुर। वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी आज रायपुर के साइंस कॉलेज परिसर में लघु उद्योग भारती द्वारा आयोजित 14वें इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश में एमएसएमई, स्टार्टअप, उद्योग, रोजगार और निवेश की संभावनाओं पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2047 तक विकसित भारत का निर्माण देश का लक्ष्य और ध्येय है। इसी विकास यात्रा में छत्तीसगढ़ भी देश के अग्रणी राज्यों के साथ कदमताल करते हुए आगे बढ़े, इसके लिए राज्य सरकार दीर्घकालिक रोडमैप के साथ काम कर रही है। वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के निर्माण के लिए स्पष्ट रोडमैप के साथ कार्य प्रारंभ किया है। विकास के साथ देश की विरासत और सांस्कृतिक पहचान को भी सशक्त बनाने पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने

कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था अब लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार है और आने वाले वर्षों में देश के विकास की गति को और तेज करने के लिए संरचनात्मक सुधारों तथा दीर्घकालिक नीतियों की आवश्यकता है। वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में योजना विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए 'अंज़ोर विजन डॉक्यूमेंट' तैयार कराया गया है। इसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि राज्य को देश के साथ कदमताल करते हुए अग्रणी राज्यों की श्रेणी में आगे बढ़ना है और राष्ट्र के विकास के महायज्ञ में छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित करनी है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 का लक्ष्य केवल दूरगामी लक्ष्य नहीं है। इसके लिए 2030 और 2035 जैसे मध्यकालिक लक्ष्यों के साथ अल्पकालिक और वार्षिक लक्ष्य भी निर्धारित किए जा रहे हैं, ताकि दीर्घकालिक विजन को चरणबद्ध तरीके से धरातल पर उतारा जा सके। मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि देश के विकास के लिए दीर्घकालिक योजना और भविष्य को ध्यान में रखकर नीतियां बनाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत ने पहले भी 21वीं सदी और विजन 2020 जैसे लक्ष्य निर्धारित किए, लेकिन उनके अनुरूप दीर्घकालिक रोडमैप और आवश्यक नीतिगत सुधारों का अभाव रहा।

मासूम की इच्छा बनी आयोग की प्राथमिकता: बालक गृह के बच्चे को जन्मदिन पर मिली मनपसंद साइकिल

डॉ. वर्णिका शर्मा ने 2 दिनों में पूरा किया अपना वादा, बच्चे के चेहरे पर लौटी मुस्कान

बाल विकास परियोजना अधिकारी ने बच्चे को साथ ले जाकर दिलाई उसकी पसंद की साइकिल

बच्चों की भावनाओं और राय का सम्मान करना ही बाल संरक्षण का मूल आधार — डॉ. वर्णिका शर्मा

रायपुर/कवर्धा, 20 सितंबर 2026। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने संवेदनशीलता और तत्परता की अनूठी मिसाल पेश की है। कवर्धा स्थित शासकीय बालक गृह के एक बच्चे की जन्मदिन की इच्छा को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने महज दो दिनों के भीतर उसकी मनपसंद साइकिल का वादा पूरा कर दिखाया। अपनी पसंद की साइकिल पाकर बच्चे का चेहरा खुशी से खिल उठा।

निरीक्षण के दौरान मनाया था जन्मदिन

प्राप्त जानकारी के अनुसार, 16 सितंबर 2026 को राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा कवर्धा प्रवास के दौरान शासकीय बालक गृह का निरीक्षण करने पहुंची थीं। निरीक्षण के दौरान उन्हें पता चला कि वहां निवासरत एक बालक का जन्मदिन है। अध्यक्ष डॉ. शर्मा ने आत्मीयता दिखाते हुए बालक के साथ उसका जन्मदिन मनाया और उससे बातचीत कर उसकी इच्छाओं व आवश्यकताओं के बारे में जाना। जब बालक से जन्मदिन के उपहार के बारे में पूछा गया, तो उसने संकोच और उत्साह के साथ एक साइकिल पाने की इच्छा जताई। इस पर अध्यक्ष ने उसे भरोसा दिलाया था कि उसकी पसंद की साइकिल जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी।

48 घंटे के भीतर पूरा किया वादा

दिए गए आश्वासन को तुरंत अमल में लाते हुए बोड़ला (कवर्धा) के बाल विकास परियोजना अधिकारी श्री नमन शर्मा बालक को स्वयं अपनी साथ ले गए और उसकी पसंद की साइकिल का चयन करवाया। चयन के पश्चात साइकिल को बालक गृह भिजवा दिया गया। साइकिल मिलते ही डॉ. वर्णिका शर्मा ने फोन पर बालक से बात की, जिस पर बच्चे ने अपनी अपार खुशी जाहिर करते हुए अध्यक्ष के प्रति आभार जताया।

सहभागिता का अधिकार ही बाल संरक्षण की मूल भावना

इस अवसर पर आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने कहा कि बाल अधिकारों की रक्षा में बच्चों की सहभागिता का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। बच्चों की बात को ध्यान से सुनना, उनकी भावनाओं व इच्छाओं को महत्व देना और उनकी राय का सम्मान करना ही बाल अधिकार संरक्षण की मूल भावना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बाल गृहों में रहने वाले बच्चों को केवल संरक्षण और बुनियादी सुविधाएं देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके समग्र व्यक्तित्व विकास, भावनात्मक आवश्यकताओं और सहभागिता के अधिकार को सुनिश्चित करना भी उतना ही आवश्यक है।

साहू समाज छत्तीसगढ़ की माटी, संस्कृति और स्वाभिमान की रीढ़: अनुज शर्मा

ग्राम बुड़ेरा में जिला व तहसील साहू समाज का भव्य शपथ ग्रहण, प्रतिभा सम्मान एवं आशीर्वाद समारोह संपन्न

धरसीवाँ/रायपुर। धरसीवाँ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बुड़ेरा स्थित माँ कर्मा मंदिर परिसर में जिला व तहसील साहू संघ (रायपुर ग्रामीण) द्वारा आयोजित भव्य 'शपथ ग्रहण, प्रतिभा सम्मान एवं आशीर्वाद समारोह' गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक अनुज शर्मा शामिल हुए, जबकि अध्यक्षता समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने की।

माँ कर्मा की पूजा-अर्चन और भव्य स्वागत

समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधायक अनुज शर्मा एवं सामाजिक प्रतिनिधियों द्वारा भक्ति व श्रद्धा की प्रतीक भक्त माता कर्मा के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलन व माल्यार्पण के साथ हुआ। तत्पश्चात सामाजिक युवाओं व पदाधिकारियों ने पारम्परिक रीति-रिवाज, ढोल-नगाड़ों और पुष्पहारों के साथ अतिथियों का आत्मीय स्वागत किया।

नवनियुक्त पदाधिकारियों ने ली सेवा की शपथ

कार्यक्रम के प्रथम चरण में जिला व तहसील साहू संघ रायपुर ग्रामीण के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण करते हुए पदाधिकारियों ने सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने, शिक्षा के प्रसार, सर्व समाज के उत्थान और कमजोर वर्गों की निस्वार्थ सहायता करने का सामूहिक संकल्प लिया।

÷शपथ एक पवित्र संकल्प, अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे सेवा÷ — अनुज शर्मा

जनसभा को संबोधित करते हुए विधायक अनुज शर्मा ने कहा, ÷साहू समाज केवल एक वर्ग या समुदाय नहीं है, बल्कि यह छत्तीसगढ़ की माटी, संस्कृति, श्रम और स्वाभिमान की सबसे मजबूत रीढ़ है। माँ कर्मा और भक्त माता राजिम का जीवन त्याग, निष्ठा और अटूट भक्ति का अद्वितीय संदेश देता है। उन्होंने नवनियुक्त कार्यकारिणी को बधाई देते हुए कहा कि शपथ ग्रहण केवल पद स्वीकार करना नहीं, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक सेवा पहुँचाने का एक पवित्र संकल्प है। विधायक शर्मा ने शिक्षा और कौशल विकास पर विशेष जोर देते हुए युवाओं से संगठित होकर समाज व प्रदेश के विकास में भागीदार बनने का आह्वान किया।

रायपुर में 'आरक्षण बचाओ रैली': SC, ST और OBC समाज ने भरी हुंकार, 19 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन

मांगें पूरी न होने पर आंदोलन व्यापक करने की चेतावनी; छत्तीसगढ़ के कोने-कोने से पहुंचे हज़ारों लोग।

रायपुर, 20 सितंबर।

राजधानी रायपुर में आज अनुसूचित जाति (ष्ट), अनुसूचित जनजाति (स्त्र) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ह्वष्ट) समुदाय द्वारा अपने अधिकारों की रक्षा के लिए विशाल 'आरक्षण बचाओ रैली' का आयोजन किया गया। प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए हज़ारों लोगों ने एकजुट होकर सामाजिक न्याय और आरक्षण से जुड़े मुद्दों पर अपनी आवाज़ बुलंद की।

शांतिपूर्ण प्रदर्शन के साथ सौंपा ज्ञापन

रैली का आयोजन पूरी तरह से अनुशासित और शांतिपूर्ण रहा। प्रदर्शन के समापन पर समाज के प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार के नाम 19 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधियों ने कहा कि एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग से जुड़े अधिकारों और आरक्षण व्यवस्था को मजबूत करने की मांग लंबे समय से की जा रही है, जिस पर सरकार को तुरंत संज्ञान लेने की आवश्यकता है।

मांगें न मानने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी

प्रदर्शनकारियों ने शासन-प्रशासन को आगाह किया कि यह ज्ञापन केवल एक ध्यानाकर्षण नहीं, बल्कि समाज की वाजिब मांगों का दस्तावेज़ है। यदि सरकार ने समय रहते इन 19 मांगों पर ठोस और सकारात्मक कार्रवाई नहीं की, तो आने वाले दिनों में इस आंदोलन को और अधिक व्यापक व उग्र रूप दिया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।

प्रदेशभर के जिलों से दिखी एकजुटता इस रैली में छत्तीसगढ़ के अलग-अलग अंचलों से आए एससी, एसटी और ओबीसी समाज के प्रमुख पदाधिकारियों, युवाओं और आम नागरिकों ने बड़ी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। रैली के माध्यम से समाज ने यह संदेश दिया कि वे अपने संवैधानिक अधिकारों और आरक्षण की सुरक्षा के लिए पूरी तरह गोलबंद हैं।

खैरागढ़ विश्वविद्यालय के कलाकारों ने चक्रधर समारोह में सजाया शास्त्रीय नृत्य का मंच

रायपुर। रायगढ़ में आयोजित 41वें अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चक्रधर समारोह-2026 की सातवीं सांस्कृतिक संध्या में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ के नृत्य संकाय के विद्यार्थियों ने ओडिसी, भरतनाट्यम और कथक की मनोहारी प्रस्तुतियों से मंच को शास्त्रीय नृत्य के विविध रंगों से सजा दिया। भाव, लय, ताल और नृत्य मुद्राओं के सुंदर समन्वय ने समारोह में मौजूद दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सांस्कृतिक संध्या की शुरुआत ओडिसी नृत्य विभाग के विद्यार्थियों की 'गणेश वंदना' से हुई। 'एकदन्तो लम्बोदरो विघ्नविनाशको देवः' की भावपूर्ण प्रस्तुति में जया निर्मलकर, सुधा योजन, प्रज्ञा प्रसाद, मीरा वर्मा, दुर्गा प्रसाद, लीना धनकर और रिकी टुडू ने नृत्य मुद्राओं के माध्यम से भगवान गणेश की आराधना को जीवंत किया। प्रस्तुति का नृत्य निर्देशन श्री सुशांत कुमार दास ने किया। इसके बाद भरतनाट्यम विभाग के विद्यार्थियों ने 'नृत्यांजलि' प्रस्तुत कर शास्त्रीय नृत्य की भाव-भंगिमाओं और लयकारी का मनोहारी प्रदर्शन किया। लावण्या आनंद द्वारा रचित इस प्रस्तुति का नृत्य संयोजन डॉ. मेदिनी होम्बल एवं श्री होरिल गौर ने किया। प्रस्तुति में होरिल गौर, प्रीति चौधरी, खुशबू भुमिज, अनुकृति सिंह, अवनि जैन, अदिति शर्मा, अंजलि चौहान और यामिनी निषाद ने सहभागिता की।

'भारत के रंग' में दिखी सांस्कृतिक विविधता

संध्या की प्रमुख प्रस्तुतियों में 'भारत के रंग' ने विशेष आकर्षण पैदा किया। भरतनाट्यम, कथक और ओडिसी जैसी शास्त्रीय नृत्य शैलियों के माध्यम से 'वंदे मातरम्' की भावभूमि को मंच पर साकार किया गया। अलग-अलग नृत्य शैलियों की विशिष्ट मुद्राओं और लय के साथ देश की सांस्कृतिक विविधता की सुंदर झलक प्रस्तुत हुई। इसका नृत्य निर्देशन श्री सुशांत कुमार दास तथा सह-निर्देशन श्री होरिल गौर ने किया।

केंद्रीय जेल दुर्ग में औचक छापा , दो मोबाइल व प्रतिबंधित सामग्री बरामद

करीब 100 से ज्यादा अधिकारियों, कर्मचारियों नें कि सघन तलाशी, जेल कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच के दायरे में ।

अंचल वर्मा - दुर्ग, उतई। जनता के गोठ।

दुर्ग - केंद्रीय जेल दुर्ग में गुरुवार सुबह जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने अचानक दुर्ग केन्द्रीय जेल परिसर में औचक निरीक्षण पर पहुंचकर हड़कंप मचा दिया। करीब सुबह 6 बजे शुरू हुई इस औचक कार्रवाई में जेल के बैरकों से लेकर शौचालय, अहाते और अन्य संभावित स्थानों की सघन जांच एवं तलाशी के दौरान जेल परिसर से दो मोबाइल फोन, चिलम, बीड़ी-सिगरेट, तंबाकू, नेलकटर और कैंची सहित प्रतिबंधित एवं आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई।

पूरी कार्यवाही की कमान दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने संभाली। उनके साथ एडीएम वीरेंद्र सिंह, एडिशनल एसपी सिटी शोभराज अग्रवाल, सीएसपी दुर्ग हर्षित मेहर सहित प्रशासन और पुलिस विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

करीब 100 से अधिक अधिकारियों - जवानों ने संभाला मोर्चा

जेल की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जिला एवं पुलिस प्रशासन की करीब 100 से अधिक अधिकारियों और जवानों की की टीम गठित कि गई थी, टीम ने सुबह ही केंद्रीय जेल परिसर को घेर लिया और बिना पूर्व सूचना के तलाशी अभियान शुरू किया कार्रवाई से

जेल प्रशासन और बंदियों के बीच अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

संयुक्त टीम ने जेल के विभिन्न बैरकों, शौचालयों, अहातों के स्थानों को खंगाला। सघन तलाशी के दौरान बंदियों के कब्जे और बैरकों के गुप्त स्थानों से दो मोबाइल फोन बरामद किए गए।

नशे के सामान के साथ कैंची और नेलकटर भी मिले

तलाशी में मोबाइल फोन के अलावा चिलम, बीड़ी, सिगरेट और तंबाकू जैसी सामग्री भी बरामद हुई। वहीं कैंची और नेलकटर जैसी वस्तुएं भी मिलीं, जिन्हें जेल की सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से प्रतिबंधित सामग्री माना जाता है।

जेल जैसे उच्च सुरक्षा वाले परिसर में प्रतिबंधित सामान और मोबाइल फोन मिलने के बाद अब यह जांच का विषय बन गया है कि आखिर ये अंदर तक कैसे पहुंचीं।

जेल कर्मचारियों की भूमिका की भी होगी जांच

कार्रवाई के बाद संयुक्त टीम ने बरामद सभी आपत्तिजनक सामग्रियों की सूची तैयार कर वैधानिक पंचनामा बनाया है। पंचनामा रिपोर्ट कलेक्टर दुर्ग को सौंपी जा रही है। इसी रिपोर्ट के आधार पर आगे की दंडात्मक एवं सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासनिक स्तर पर इस बात की भी जांच की जाएगी कि जेल के अंदर प्रतिबंधित सामग्री पहुंचने में कहीं किसी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति की भूमिका तो नहीं रही। यदि जांच में किसी की मिलीभगत या लापरवाही सामने आती है तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। औचक सुरक्षा व्यवस्था की जांच और प्रतिबंधित गतिविधियों पर अंकुश लगाने की दिशा इस कार्यवाही को महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है ।

स्वामी,मुद्रक,प्रकाशक,संपादक-शुभम वर्मा द्वारा मकान नंबर 411, देवनगर, आदिवासी छात्रावास के सामने, शिव शंकर होटल के पीछे महादेव घाट रायपुरा, रायपुर (छ.ग.) से प्रकाशित एवं छत्तीसगढ़ प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स अनंत विहार कालोनी,दलदल सिवनी मार्ग -मोवा रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित। (पी.आर.बी. एक्ट के तहत समाचार चयन के लिये जिम्मेदार) फोन:-9300870270, 9425520408 jantakegoth@gmail.com